Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 338
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शनिवार, 13 दिसम्बर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

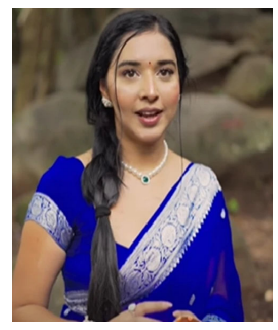

3 महाराष्ट्र में माइक्रोसॉफ्ट का भारी निवेश,...

4 दबाव के दायरे में पिसता बचपन, जीवन ...

7 बहरीन के तेज गेंदबाज अली दाऊद का ...

संक्षिप्त न्यूज

उड़ान संकट के बाद इंडिगो ने शुरू की बड़ी कार्रवाई, बाहरी एविएशन विशेषज्ञ करेंगे मामले की जांच

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में हाल के दिनों में सामने आए भारी उड़ान संकट के बाद अब कंपनी के बोर्ड ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लगातार हो रही उड़ान देरी, रद्दीकरण और यात्रियों की बढ़ती नाराजगी के बीच इंटरग्लोब एविएशन के बोर्ड ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह एक बाहरी, स्वतंत्र एविएशन विशेषज्ञ से पूरे मामले की गहन जांच कराएगा। यह फैसला ऑपरेशनल संकट के बाद लिया गया है, जिसने एयरलाइन की विश्वसनीयता को झटका दिया है।

एयरलाइन ने बयान जारी कर बताया कि चीफ एविएशन एडवाइजर्स एलएलसी, जो कैप्टन जॉन इल्सन की अगुवाई में काम करती है, को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। कैप्टन इल्सन लंबा अंतरराष्ट्रीय अनुभव रखने वाले वरिष्ठ एविएशन विशेषज्ञ हैं।

उड़ान संचालन पर पड़े बड़े असर

इंडिगो में 2 दिसंबर से शुरू हुए ऑपरेशनल संकट ने पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर दिया था। हवा में उपलब्ध उड़ानों की कमी, क्रू मैनेजमेंट में गड़बड़ी और एफडीटीएल (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) के दूसरे चरण को लागू करने में लापरवाही की वजह से बड़ी संख्या में उड़ानें देरी से चलीं या रद्द करनी पड़ीं। इन घटनाओं ने एयरलाइन की समयबद्धता और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी जाएगी

इंडिगो ने कहा है कि कैप्टन जॉन इल्सन जल्द से जल्द जांच शुरू करेंगे और एक विस्तृत, व्यापक रिपोर्ट बोर्ड को सौंपेंगे। रिपोर्ट में संकट की मूल वजहों का विश्लेषण, एयरलाइन के संचालन में हुई चूकें, पायलट और क्रू मैनेजमेंट की खामियां, और इन्हें सुधारने के उपाय शामिल होंगे। बोर्ड चाहता है कि भविष्य में इस तरह का संकट दोबारा न हो, इसलिए जांच पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी।

सरकार का बड़ा फैसलाः

मनरेगा का नाम बदलकर किया 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना', काम के दिन भी बढ़ाए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़ी देश की सबसे बड़ी योजना मनरेगा को नया रूप देने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने वाला बिल मंजूर किया गया। सरकार का कहना है कि यह बदलाव ग्रामीण रोजगार और विकास को नई दिशा देने के लिए किया जा रहा है।

मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य काम की मांग कर सकते हैं। पंचायत स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। काम अलग-अलग तरह के होते हैं। जैसे तालाब बनाना, सड़क की मरम्मत, नाला खुदाई, बागवानी, मिट्टी कार्य और अन्य सामुदायिक काम। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना रोजगार देने और आजीविका को सुरक्षित करने का बड़ा जरिया है।

क्यों बढ़ाए गए काम के दिन

सरकारी सूत्रों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में महंगाई और नौकरी की कमी को देखते हुए काम के दिनों को 125 करने का फैसला लिया गया है। सरकार चाहती है कि गांवों में रहने वाले परिवारों को अतिरिक्त काम मिले, ताकि उनकी आमदनी बढ़े और पलायन कम हो। बताया गया कि काम के दिनों की बढ़ोतरी से गांवों में मजदूरी का चक्र मजबूत होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में गति आएगी।

नाम बदलने के पीछे का तर्क

सूत्रों का कहना है कि योजना का नया नाम 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' महात्मा गांधी की ग्रामीण स्वावलंबन की विचारधारा को दर्शाने के लिए रखा गया है। सरकार चाहती है कि गांधी के ग्राम स्वराज के सिद्धांत को रोजगार से जोड़ा जाए। हालांकि, योजना की संरचना वही रहेगी। बदलाव सिर्फ नाम और काम के दिनों के रूप में लागू किया जाएगा।

बिल को अब संसद में रखा जाएगा

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब यह बिल संसद में पेश किया जाएगा। विधेयक पास होते ही कानून में बदलाव लागू हो जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि बिल के साथ योजना के नियमों में भी संशोधन होंगे, ताकि नए नाम और काम के दिनों को आधिकारिक रूप से लागू किया जा सके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार, अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार ग्रामीण परिवारों को काफी राहत देगा। इससे उनकी आय बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के अवसर मजबूत होंगे। मनरेगा के तहत काम मिलने से ग्रामीण क्षेत्र में नकदी का प्रवाह बढ़ता है, जिससे बाजार और छोटे व्यवसायों को भी लाभ होता है।

सरकार ने हटाए जाने वाले 71 पुराने कानूनों को किया खत्म, संसद में भी आएगा नया विधेयक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के कानूनी ढांचे को सरल और अपडेटेड बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन कानूनों को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिनका अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। सरकार ने कुल 71 पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। इनमें ऐसे कानून भी शामिल हैं जो दशकों पहले के हैं और अब किसी काम के नहीं हैं।

सरकार की जानकारी के अनुसार, कुल 71 कानूनों में से 65 कानून सिर्फ पुराने संशोधन (अमेंडमेंट) हैं, जिन्हें पहले ही मूल कानून में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा 6 मूल कानून (प्रिंसिपल एक्ट) भी खत्म किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, इन हटाए जाने वाले कानूनों में से कम से कम एक ब्रिटिश काल का पुराना कानून भी शामिल है। इनका अब किसी प्रकार का प्रशासनिक या कानूनी उपयोग नहीं है।

क्यों जरूरी थी पुरानी कानूनों की सफाई

सरकार का कहना है कि जब संसद कोई संशोधन पास कर देती है, तो वह मूल कानून में शामिल हो जाता है। इसके बावजूद वह संशोधन अलग से भी रिकॉर्ड में बना रहता है, जिससे कानूनों की सूची में अनावश्यक भीड़ हो जाती है। इससे सरकारी सिस्टम में भ्रम बढ़ता है और आम लोगों के लिए कानूनों को समझना मुश्किल होता है।

हटाए जाने वाले कानूनों की असल वजह

कानून मंत्रालय के अनुसार, जिन कानूनों को हटाया जा रहा है वे अब 'उपयोगहीन' हैं। न तो उनका उपयोग अदालतों में हो रहा है और न ही किसी सरकारी कामकाज में। अधिकारियों ने साफ किया है कि यह कदम औपनिवेशिक कानूनों को हटाने का अभियान नहीं है, बल्कि उन कानूनों को हटाने का है जो अब भारत के प्रशासनिक ढांचे के लिए जरूरी नहीं रहे।

अमित शाह ने अंडमान-निकोबार को बताया 'तपोभूमि'; बोले- सावरकर ने अपने जीवन के कठिन वर्ष यहीं बिताए

श्री विजयपुरम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वातंत्र्यवीर सावरकर के 'सागरा प्राण तळमळला' गीत के 115 वर्ष पूर्ण होने पर अंडमान और निकोबार के श्री विजयपुरम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि अंडमान और निकोबार सिर्फ द्वीपों की एक श्रृंखला नहीं है। यह असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, समर्पण और देशभक्ति से बनी एक 'तपोभूमि' है। सावरकर की कविता 115 वर्ष पूरे होने पर गृह मंत्री ने कहा, 'हम सब एक पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता से पहले, कोई भी यहां अपनी मर्जी से नहीं आता था। जिन्हें भी यहां लाया जाता था, उनका परिवार उन्हें भूल जाता था। उस दौर में, कोई यह नहीं सोचता था कि 'काला पानी' में सजा काटने के बाद कोई वापस लौट भी सकता है।' उन्होंने आगे कहा, 'जब तक वे लौटते, उनका शरीर, मन और आत्मा इतनी कमजोर हो जाती थी कि वे कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते थे। लेकिन आज, यह सभी भारतीयों के लिए एक तीर्थस्थल है क्योंकि वीर सावरकर ने अपने जीवन के सबसे कठिन वर्ष यहीं बिताए।' अमित शाह ने कहा, 'यहां कई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैंने सेलुलर जेल के रिकॉर्ड का गहन अध्ययन किया है; केवल दो ही ऐसे प्रांत हैं जिनके स्वतंत्रता सेनानियों को यहां फांसी नहीं दी गई।' उन्होंने कहा, 'यह एक बहुत बड़ा अवसर है। इस 'तपोभूमि' पर वीर सावरकर की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण मोहन भागवत ने किया, जो उस संगठन के सरसंघचालक हैं जो सही मायने में सावरकर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है।

पूरे साल कैपिंग असंभवष्ठसंसद में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया, क्यों नहीं फिक्स हो सकता फेयर रेट

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि सरकार के लिए पूरे देश में हवाई किराए पर सीमा लगाना व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि एक अनियंत्रित बाजार अंततः उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता है और फेस्टिवल सीजन के दौरान टिकटों की कीमतें आमतौर पर बढ़ जाती हैं। फेस्टिवल सीजन के दौरान विशिष्ट मार्गों और विशेष समयों पर मांग बढ़ने के कारण हवाई किराए में आमतौर पर वृद्धि होती है। ये उतार-चढ़ाव मौसमी होते हैं, और किसी भी विशेष मार्ग पर पूरे वर्ष के लिए किराए को स्थिर रखना संभव नहीं है। बाजार की मांग और आपूर्ति स्वाभाविक रूप से हवाई किराए को नियंत्रित करती हैं।

मंत्री के अनुसार, जब उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, तब इसका उद्देश्य इस क्षेत्र को विकसित होने देना था।' उन्होंने आगे कहा, 'जिन देशों ने असाधारण वृद्धि देखी है, उन सभी ने बाज़ारों को उदारीकृत किया है। इससे अधिक कंपनियों को प्रवेश करने का प्रोत्साहन मिलता है और सहयोग के द्वार खुलते हैं। इससे बाज़ार की गतिशीलता को स्वाभाविक रूप से काम करने की अनुमति मिलती है, जिससे मांग और आपूर्ति अपनी स्वाभाविक भूमिका निभा पाती हैं। अंततः, इसका सबसे अधिक लाभ यात्रियों को ही मिलता है।

डिगो संकट के बीच हवाई किराए को विनियमित करने के लिए पेश किए गए एक निजी विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसके कारण टिकटों की कीमतें आसमान छू गईं, मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विनियमन मुक्त करने का मूल विचार अभी भी कायम है, और 'यदि हम नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता इसे विनियमन मुक्त रखना है ताकि अधिक खिलाड़ी बाजार में प्रवेश कर सकें।

वायु प्रदूषण पर संसद में राहुल गांधी ने सरकार-विपक्ष की संयुक्त कार्रवाई की जताई इच्छा

नई दिल्ली। संसद में शुक्रवार को वायु प्रदूषण पर एक गंभीर और सीधे मुद्दे की बातचीत शुरू हुई है, जिसमें विपक्ष और सरकार पहली बार बिना टकराव के आगे बढ़ने की इच्छा दिखाते नजर आए हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता पर तात्कालिक और सर्वदलीय चर्चा की मांग करते हुए कहा कि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति नहीं, बल्कि साझा प्रयासों की आवश्यकता है।

राहुल गांधी ने कहा कि देश के कई बड़े शहरों में लोग जहरीली हवा की चादर के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं। उन्होंने चिंता जताई कि लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे हैं, बुजुर्ग सांस लेने तक में संघर्ष कर रहे हैं और कैंसर जैसे मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राहुल ने कहा कि यह वैचारिक मतभेदों का विषय नहीं है, बल्कि वह मुद्दा है जिस पर सत्ता और विपक्ष दोनों की सहमति बन सकती है। उनका कहना था कि यह चर्चा इस आधार पर होनी चाहिए कि भविष्य में देश को बचाने के लिए हम मिलकर क्या कदम उठा सकते हैं, न कि एक-दूसरे पर आरोप लगाने पर।

बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार की ओर से इस चर्चा के लिए तत्परता जताई और कहा कि लोकसभा की बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी इस पर समय तय कर सकती है। गौरतलब है कि यह पहली बार है जब वायु प्रदूषण को लेकर संसद के भीतर दोनों पक्षों में एक सकारात्मक माहौल दिखाई दिया है।

इसके बाद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में वायु प्रदूषण को 'राष्ट्रीय आपदा' बताते हुए कहा कि इसे तत्काल, व्यापक और ठोस राष्ट्रीय कार्ययोजना की आवश्यकता है। उन्होंने लिखा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी है और वे प्रधानमंत्री के साथ मिलकर इस दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं।

वहीं वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी राहुल के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि यह समस्या बहुत लंबे समय से बढ़ रही है और अब सभी दलों को मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए।

इस बीच, बता दें कि विश्व बैंक ने हाल ही में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्वच्छ हवा से जुड़े दो बड़े कार्यक्रमों के लिए लगभग 600 मिलियन डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। विश्व बैंक इंडिया के कार्यकारी निदेशक पॉल प्रूसी ने कहा कि दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर असर डाल रहा है, और ये कार्यक्रम न सिर्फ वायु गुणवत्ता में सुधार करेंगे बल्कि युवाओं और महिलाओं के लिए हरित नौकरियों के अवसर भी तैयार करेंगे।

इधर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। शुक्रवार को शहर के ऊपर घना स्मॉग छाया रहा और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 332 हो गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। दिल्ली के 30 से अधिक मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' दर्ज की गई, जबकिजहांगीरपुरी में एक्यूआई 405 तक पहुंच गया जो 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है। राजधानी में लगातार बिगड़ती हवा लोगों के स्वास्थ्य, आवाजाही और रोजमर्रा जिंदगी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

अमृतसर में हाई अलर्ट, 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तानी संगठन का मेल सामने आया

अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार को कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले, जिसके चलते छात्रों को स्कूलों से बाहर निकाला गया और अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। जिला प्रशासन ने अमृतसर के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूलों की ओर दौड़ पड़े। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने एक बयान में कहा कि शहर और ग्रामीण इलाकों के कुछ स्कूलों को संदिग्ध ईमेल मिले हैं। प्रत्येक स्कूल में एक राजपत्रित अधिकारी तैनात किया गया है और तोड़फोड़ रोधी जांच जारी है। साइबर पुलिस स्टेशन ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है। इस बीच, अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि स्कूलों को मिली बम की धमकियां झूठी थीं और मामले की जांच जारी है।

भुल्लर ने कहा कि अमृतसर जिले के आसपास के ग्रामीण इलाकों में कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिलीं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजा गया और परिसरों को सुरक्षित कर लिया गया... धमकियां झूठी निकलीं...

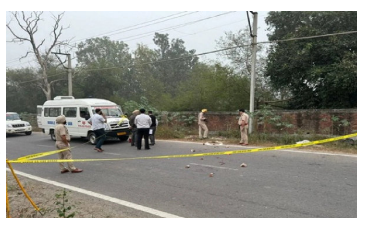

जांच जारी है। इस बीच, एडीसीपी-2, सिरिवेन्नेला ने बताया कि अधिकारियों ने तोड़फोड़ रोधी जांच की है और चिंता की कोई बात नहीं है। दस से बारह स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिलीं। हमने सभी स्कूलों में तोड़फोड़ रोधी जांच की है। चिंता की कोई बात नहीं है; यह सिर्फ एक झूठी कॉल थी। हम पता लगा रहे हैं कि ये ईमेल किसने भेजे हैं।

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले लक्ष्मी नगर स्थित दिल्ली के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके चलते स्कूल को खाली कराया गया। यह धमकी सुबह करीब 10:40 बजे फोन पर मिली, जिसमें दावा किया गया था कि लवली पब्लिक स्कूल के अंदर एक विस्फोटक उपकरण लगाया गया है। सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस, अग्निशमन विभाग और अन्य आपातकालीन एजेंसियों को दी गई। इसके जवाब में कई अग्निशमन गाड़ियां, बम निरोधक दस्ते, खोजी कुत्ते और पुलिस दल मौके पर भेजे गए। अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल से बाहर निकाल लिया गया और परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया।

कोई भी जबरन वक्फ संपत्तियों पर कब्जा नहीं कर सकता : ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वक्फ संपत्तियों को मौजूदा नियमों के तहत सख्ती से संरक्षित किया जाएगा और कोई भी उन्हें जबरन अधिग्रहित नहीं कर सकता है।

नदिया के कृष्णानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई कल्याणकारी उपाय किए हैं, जिनमें 10,000 कब्रिस्तानों का निर्माण और ओबीसी आरक्षण लाभों का विस्तार शामिल है। उन्होंने कहा, 'हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि वक्फ संपत्ति में नियमों का पालन होगा। अब मुतवल्ली (मस्जिद के न्यासी) इसका पालन करेंगे। हम किसी को भी वक्फ संपत्ति हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे।' विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि चुनाव में मुस्लिम समुदाय से भारी समर्थन हासिल करने के बावजूद मुख्यमंत्री ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने दावा किया, 'जिसे 2021 में 92 प्रतिशत और 2024 में 91 प्रतिशत मुस्लिम वोट मिले थे, उसने अब वक्फ के मुद्दे पर समुदाय को गड्ढे में धकेल दिया है।'

अधिकारी ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने वक्फ की कई एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, यही वजह है कि सरकार केंद्र के 'उम्मीद' पोर्टल पर संपत्ति के आंकड़े अपलोड करने की प्रक्रिया में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां अन्य राज्यों ने वक्फ संपत्ति के विवरण तुरंत अपलोड कर दिए हैं, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की 'उदासीनता' के कारण लगभग 80,000 संपत्तियां लंबित पड़ी हैं।

56 पूर्व न्यायाधीशों की महाभियोग पर कड़ी प्रतिक्रिया, कहा- न्यायपालिका को डराने का प्रयास

नई दिल्ली। 56 पूर्व न्यायाधीशों ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ संसद में विपक्षी सांसदों द्वारा लाए गए महाभियोग नोटिस का विरोध करते हुए एक खुला पत्र लिखा। अपने बयान में पूर्व न्यायाधीशों ने महाभियोग की इस कार्रवाई को समाज के एक विशेष वर्ग की वैचारिक या राजनीतिक अपेक्षाओं से असहमत न्यायाधीशों को डराने-धमकाने का एक बेशर्म प्रयास बताया। हम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और माननीय उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन पर महाभियोग चलाने के प्रयास का घोर विरोध करते हैं, जिसे कुछ संसद सदस्यों और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। यह समाज के एक विशेष वर्ग की वैचारिक और राजनीतिक अपेक्षाओं के अनुरूप न चलने वाले न्यायाधीशों को धमकाने का एक घिनौना प्रयास है। बयान में कहा गया कि यदि ऐसे प्रयास को आगे बढ़ने दिया गया, तो यह हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ों को ही नष्ट कर देगा। यदि हस्ताक्षरकर्ता संसद सदस्य(सदस्यों) द्वारा बताए गए कारणों को अक्षरशः मान भी लिया जाए, तो भी वे महाभियोग जैसे दुर्लभ, असाधारण और गंभीर संवैधानिक उपाय का सहारा लेने को पूरी तरह से अपर्याप्त साबित करते हैं। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि कथित फैसले के आधार पर किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रयास की अनुमति देना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा होगा।

महाभियोग तंत्र का मूल उद्देश्य न्यायपालिका की अखंडता को बनाए रखना है, न कि इसे दबाव बनाने, संकेत देने और प्रतिशोध का हथियार बनाना। न्यायाधीशों को राजनीतिक अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने के लिए पद से हटाने की धमकी का इस्तेमाल करना संवैधानिक सुरक्षा को डराने-धमकाने का साधन बनाना है। ऐसा दृष्टिकोण लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी और कानून के शासन के लिए घोर दंड है।

बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी विधायकों को चर्चा के लिए दिल्ली आने को कहा : बीरेन सिंह

इंफाल। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी विधायकों को राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आने को कहा है।

सिंह ने पत्रकारों से कहा, ''भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। पार्टी नेताओं ने विधायकों को रविवार को राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया है। मेरा मानना ??है कि यह सरकार गठन से संबंधित हो सकता है, लेकिन अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हममें से कई लोग (दिल्ली के लिए) रवाना हो रहे हैं।''सिंह ने यह भी उम्मीद जताई कि राज्य में जल्द एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो सकता है। मई 2023 से लेकर अब तक मेइती और कुकी-जो समुदायों के बीच हुई जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है, जिसे निलंबित कर दिया गया है। मणिपुर में 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 37 विधायक हैं।

राजनीति बंद कर समाधान ढूंढ़ें, प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रदूषण पर चर्चा की मांग का किया स्वागत

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग का स्वागत किया और जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इससे पीड़ित हैं। शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने इस बात पर बल दिया कि दिल्लीवासियों को ऐसा लगता है मानो वे हर दिन जहरीली हवा में सांस ले रहे हों और भाजपा के सत्ता में होने के बावजूद इस मुद्दे पर बहस न होने की आलोचना करते हुए कहा कि यह कभी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमले का एक प्रमुख मुद्दा हुआ करता था।

एएनआई से बात करते हुए चतुर्वेदी ने कहा मैं इसका स्वागत करता हूं। ऐसा लगता है जैसे हम हर दिन जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। आम आदमी

पार्टी के सत्ता में रहते हुए भाजपा इस मुद्दे पर चर्चा करती थी, लेकिन सरकार बनने के बाद भी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इससे पीड़ित हैं। इस पर राजनीति करने के बजाय हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिगड़ते वायु प्रदूषण संकट पर संसद में व्यापक चर्चा के राहुल गांधी के आह्वान का समर्थन करते हुए कहा कि यह मुद्दा अत्यावश्यक है और 'सरकार को एक अच्छी कार्य योजना बनानी चाहिए' और उसे आगे बढ़ाना चाहिए।

पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वायु प्रदूषण हर साल बढ़ता जा रहा है और इसके लिए एक समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह सहमत हूं, और मुझे लगता है कि सभी सहमत होंगे। सरकार ने भी कहा है कि हम सभी को इस पर चर्चा करनी चाहिए और एक कार्य योजना बनानी चाहिए। यह हर साल बढ़ रहा है। हम अन्य सभी विषयों पर चर्चा करते हैं, इसलिए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और कुछ ठोस परिणाम निकलना चाहिए। अगर सरकार एक अच्छी कार्य योजना बनाती है और उसे आगे बढ़ाती है, तो यह बहुत अच्छा होगा। इससे पहले आज, राहुल गांधी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और सभी राजनीतिक दलों से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में खतरनाक प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए मतभेदों को भुलाने का आग्रह किया।

मध्य रेल की आरपीएफ ने असाधारण खोज कौशल का प्रदर्शन किया - चोरी का मामला मात्र 3 दिनों में सुलझाया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

जांच कौशल और तकनीकी विशेषज्ञता का शानदार प्रदर्शन करते हुए, मध्य रेल की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) टीम ने मात्र 3 दिनों में चोरी का एक मामला सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। दिनांक 20 सितंबर 2025 को जलगांव के पास ट्रेन संख्या 12167-एलटीटी-बनारस एक्सप्रेस में चोरी की घटना दर्ज की गई, जिसमें एक महिला यात्री का लगभग 3,00,000 रुपये मूल्य का सोने का आभूषणों से भरा पर्स चोरी हो गया। जीआरपी/भुसावल/जलगांव में मामला दर्ज किया गया।

सहायक सब-इंस्पेक्टरों और कांस्टेबलों सहित आरपीएफ कर्मियों की एक विशेष टीम ने निरंतर तकनीकी और मानवीय खुफिया प्रयासों के माध्यम से मामले को सुलझाया और मुख्य आरोपी महेश लिंगायत को मात्र 3 दिनों के भीतर यानी 23 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और साथ ही दिनांक 26.12.2024 (लगभग 9 महीने पहले) को हुई ट्रेन संख्या 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस में हुई एक अन्य चोरी की घटना में भी अपनी संलिप्तता का खुलासा किया, जिसमें एक यात्री का 9,64,400 रुपये मूल्य का आभूषणों से भरा बैग चोरी हो गया था। यह मामला भी जीआरपी भुसावल/जलगांव में दर्ज किया गया था।

जीआरपी ने आरपीएफ की सहायता से बाद में दो और आरोपियों, राजकुमार विश्वकर्मा और मनोज जाधव को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

आरपीएफ टीमों ने जीआरपी के साथ मिलकर दोनों मामलों को सुलझाने में उत्कृष्ट खोज कौशल, सटीक खुफिया विश्लेषण, निगरानी तकनीक का प्रभावी उपयोग और समन्वित टीम वर्क का प्रदर्शन किया है।

ये मामले मध्य रेल आरपीएफ की व्यावसायिकता, ईमानदारी और तकनीकी दक्षता का प्रमाण हैं।

मध्य रेल यात्रियों से अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील करता है और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में सहायता के लिए 139 डायल करें।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं अजमेर के बीच चलाएगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अजमेर में उर्स फेस्टिवल के लिए यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को समायोजित करने के लिए बांद्रा टर्मिनस एवं अजमेर स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09027/09028 बांद्रा टर्मिनस - अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल (04 फेरे)

ट्रेन संख्या 09028 बांद्रा टर्मिनस - अजमेर स्पेशल सोमवार और गुरुवार, 22 एवं 25 दिसंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 12:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:20 बजे अजमेर पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09028 अजमेर - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल मंगलवार और शुक्रवार, 23 एवं 26 दिसंबर, 2025 को अजमेर से 10:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, दहानू रोड, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर और नसीराबाद स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09027 की बुकिंग 14 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

दिव्यांग विद्यार्थियों का वार्षिक क्रीड़ा दिवस उत्साहपूर्वक संपन्न - एनएमयू ईटीसी केंद्र

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई महानगरपालिका के ईटीसी दिव्यांग शिक्षण, प्रशिक्षण और सेवा केंद्र द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को समाज में अपनी अलग पहचान बनाने व आत्मनिर्भर बनने के लिए विविध उपक्रम लगातार चलाए जाते हैं। इसी क्रम में, ईटीसी केंद्र के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक क्रीड़ा दिवस का आयोजन किया गया, ताकि दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह खेलकूद का आनंद ले सकें। सभी विद्यार्थियों ने इस आयोजन में हर्ष और उमंग के साथ भाग लिया।

यह क्रीड़ा दिवस प्रातः 8 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक ईटीसी केंद्र के प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सलामी देकर की गई। आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त आयुक्त श्री सुनील पवार के नियंत्रण में तथा ईटीसी केंद्र की संचालिका डॉ. अनुराधा बाबर के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। ठाणे जिले के प्रसिद्ध मल्लखंब प्रशिक्षक श्री किशोर माठरे, केंद्र प्रबंधक तथा केंद्रप्रमुख द्वारा दीपप्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर ईटीसी केंद्र के बहरे, मानसिकदृष्ट्या मंद, दृष्टिहीन और बहुविध दिव्यांग विभागों के 2 से 18 वर्ष आयु समूह के विद्यार्थियों ने उत्साह से सहभाग लिया। विद्यार्थियों की विविध शारीरिक व मानसिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी क्षमता प्रदर्शित करने हेतु अनेक सरल और मनोरंजक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें दौड़, हाथ में चमचे पर नींबू रखकर चलना, खरगोश की तरह उछलना, मनोरा निर्माण, तथा मृदु गेंद फेंकना जैसी प्रतियोगिताएं शामिल थीं।

प्रतियोगिताओं में विजयी विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र और पदक ईटीसी केंद्र की संचालिका तथा सहायक आयुक्त डॉ. अनुराधा बाबर के हस्ते प्रदान किए गए। विद्यार्थी राजा महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों ने पंच के रूप में कार्य कर सहयोग दिया। उन्हें भी सम्मानपत्र प्रदान किए गए। आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे का मत है कि दिव्यांग बच्चों की जन्मजात क्रीड़ा प्रतिभा का विकास उनके सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार ने भी कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से दिव्यांग बच्चों की सुप्त क्षमताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस अनुषंग में इस वार्षिक क्रीड़ा दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की पूरी योजना मानसिकदृष्ट्या मंद विभाग के शैक्षणिक प्रबंधक दीपक नवघरे, बहरे विभाग की शैक्षणिक प्रबंधिका विद्या कदम तथा क्रीड़ा शिक्षक श्री सुभाष भुसारा और समीर माठरे ने तैयार की। केंद्र के सभी कर्मचारियों ने अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ पूर्ण निष्ठा से निभाकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। विशेष रूप से, दिव्यांग विद्यार्थियों के पालकों ने भी इस गतिविधि का आनंद लिया।

रेलवे पंढरपुर-तिरुपति के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेनें चलाएगा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रेलवे ने पंढरपुर और तिरुपति के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसका विवरण निम्नानुसार है–

पंढरपुर-तिरुपति साप्ताहिक विशेष ट्रेनें

1. ट्रेन संख्या 07012 तिरुपति-पंढरपुर साप्ताहिक विशेष।दिनांक 20.12.2025 से 31.12.2025 तक हर शनिवार । प्रस्थानः तिरुपति से शाम 04:40 बजे । पहुंचः अगले दिन शाम 06:50 बजे पंढरपुर । ठहरावः रेणिगुंटा, राजमपेटा, ओंटिमिट्ट, कडपा, येरगुंटला, ताडिपत्रि, गूटी, डोन, कर्नूल सिटी, गदवाल, वनपर्ती रोड, महबूबनगर, जडचर्ला, शादनगर, उमदानगर, काचीगुडा, सिकंदराबाद, बेगमपेट, लिंगमपल्ली, शंकरपल्ली, विकाराबाद, जहीराबाद, बीदर, भालकी, उदगीर, लातूर रोड, लातूर, धाराशिव, बार्शी टाउन, कुर्डूवाडी, मोडलिंब। 2. ट्रेन संख्या 07032 पंढरपुर-तिरुपति साप्ताहिक विशेष । दिनांक 21.12.2025 से 28.12.2025 तक हर रविवार। प्रस्थानः पंढरपुर से रात 08:00 बजे । पहुंचः अगले दिन रात 10:30 बजे तिरुपति । ठहरावः मोडलिंब, कुर्डूवाडी, बार्शी टाउन, धाराशिव, लातूर, लातूर रोड, उदगीर, भालकी, बीदर, जहीराबाद, विकाराबाद, शंकरपल्ली, लिंगमपल्ली, बेगमपेट, सिकंदराबाद, चर्लपल्ली, नल्लगोंडा, मिर्यालगुडा, नडीकुडी, सत्तनपल्ली, गुंटूर, तेनाली, बापटल्ला, ओंगोल, नेल्लूर, गुडूर, श्री कालहस्ती, रेणिगुंटा । कोच संरचना 20.12.2025 से 03.01.2026 तक। 1 फर्स्ट एसी कम एसी-II टियर
3 एसी-III टियर
14 स्लीपर क्लास
4 जनरल सेकेंड क्लास
2 गार्ड कम ब्रेक वैन
(कुल 24 कोच)
04.01.2026 से 01.02.2026 तक
1 एसी-II टियर
3 एसी-III टियर
14 स्लीपर क्लास
4 जनरल सेकेंड क्लास
2 गार्ड कम ब्रेक वैन
(कुल 24 कोच)

आरक्षण सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और IRCTC वेबसाइट पर खोला जाएगा।

अनारक्षित कोच का टिकट स्टेशन बुकिंग काउंटर और UTS ऐप के माध्यम से भी लिया जा सकता

पश्चिम रेलवे का बोरीवली और गोरेगांव स्टेशनों के बीच रविवार को जम्बो ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रेल पथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा बोरीवली और गोरेगांव स्टेशनों के बीच रविवार, 14 दिसम्बर, 2025 को 10.00 बजे से 15.00 बजे तक अप एवं डाउन स्लो लाइनों पर पांच घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान गोरेगांव और बोरीवली के बीच अप एवं डाउन स्लो लाइन की सभी ट्रेनें फास्ट लाइनों पर चलाई जाएंगी। ब्लॉक के कारण कुछ अप एवं डाउन उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी तथा अंधेरी और बोरीवली की कुछ ट्रेनें गोरेगांव स्टेशन तक हार्बर लाइन पर चलाई जाएंगी। ब्लॉक अवधि के दौरान बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, 2, 3 और 4 से कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी।

मध्य रेल, एलटीटी मुंबई और बनारस के बीच एक अतिरिक्त विशेष ट्रेन सेवा चलाएगा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे एलटीटी मुंबई और बनारस के बीच एक अतिरिक्त विशेष ट्रेन सेवा चलाएगा। विवरण इस प्रकार हैः

एलटीटी मुंबई - बनारस विशेष (1 सेवा)

01081 विशेष ट्रेन दिनांक 14.12.2025 को सुबह 08:25 बजे एलटीटी मुंबई से प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 16:05 बजे बनारस पहुंचेगी।

ठहराव : कल्याण, नाशिक रोड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्ज़ापुर और वाराणसी जंक्शन

संरचनाः 1 एसी-प्रथम श्रेणी सह एसी-II टियर, 1 एसी-II टियर, 6 एसी-III टियर, 2 एसी-III टियर इकोनॉमी, 5 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 1 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड की ब्रेक वैन और 1 जेनरेटर कार।

आरक्षणः

विशेष ट्रेन संख्या 01081 के लिए विशेष शुल्क पर बुकिंग सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और

वेबसाइट http://www.irctc.co.in पर पहले से ही शुरू है।

उक्त विशेष ट्रेन के ठहराव एवं समय की विस्तृत जानकार के लिए, कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं या NTES ऐप डाउनलोड करें। यात्रियों से अनुरोध है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैध टिकटों के साथ यात्रा करें और इस विशेष ट्रेन सेवा का लाभ उठाएं।

पश्चिम रेलवे
वार्षिक रखरखाव अनुबंध

डिविजनल रेलवे मैनेजर (S&T) मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400 008 टेंडर नंबर: SG623/1783/WA-R2 तारीख 11.12.2025 आमंत्रित करता है। **काम का नामः** मुंबई डिविजन के चर्चगेट-विरार सेक्शन के अलग-अलग स्टेशनों पर 04 साल के लिए टेलीटेक मेक के सबअर्बन ट्रेन इंडिकेटर्स का कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (CAMC)। **काम की कीमतः** 20,32,031.63/- **बिड सिक्योरिटीः** 40,700/- **ई-टेंडर डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए बंद करने का समय और तारीखः** 02.01.2026, 15.00 बजे तक। **ई-टेंडर खोलने का समय और तारीखः** 02.01.2026 को 15.30 बजे। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 0887

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन

डिविजनल रेलवे मैनेजर (रोलिंग स्टॉक) शेड कारशेड मुंबई सेंट्रल डिवीजन, वेस्टर्न रेलवे, मुंबई 400034 ई-टेंडर नोटिस नंबर DRM/RS/2025-26/11 तारीखः 09.12.2025 आमंत्रित करता है- **काम का नामः** तीन साल के लिए EMU कारशेड BCT, KILE और लाइन में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन। **काम की अनुमानित लागतः** 13,61,625.6/-**ईएमडी**-27,200/- **जमा करने की तारीख और समयः** 02.01.2026, 15:00 बजे तक। **खुलने की तारीख और समयः** 02.01.2026 को 15:30 बजे। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 0882

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे
इलेक्ट्रिकल पावर का काम

सीनियर DEE/P/BCT टेंडर नोटिस नंबरः EL-81-933-WA-65 तारीख 08.12.2025 आमंत्रित करता है। **काम और जगहः** उधना - उकैसनगढ़ सेक्शन- ADEN-VYARA सेक्शन के तहत अलग-अलग RUB पर सीपेज, पानी के बहाव और पानी जमा होने से बचाने के लिए अप्रोच दीवारों, सड़कों, मिट्टी के काम, ग्राउटिंग वगैरह को ऊपर उठाने के संबंध में इलेक्ट्रिकल (पावर) का काम। **काम की लगभग लागतः** 23,90,617/-ईएमडी- 47,800/- **जमा करने की तारीख और समयः** 07.01.2026, 15.00 बजे तक। **खुलने की तारीख और समयः** 07.01.2026 को 15.30 बजे। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 0880

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

बीड जिले में बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, एक व्यक्ति की मौत

दिव्यांश
मुंबई(संवाददाता)

बीड जिले में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) द्वारा संचालित एक बस की टक्कर से मोटरसाइकिल चला रहे 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

यह घटना बुधवार शाम को बीड-अहिल्यानगर रोड पर काकाधिरा के पास हुई। मृतक की पहचान बीड तहसील के काकाधीरा निवासी विश्वास उर्फ राजाभाऊ शिवाजी बागलेन के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, बागलेन बीड से अपने गांव की ओर मोटरसाइकिल से जा रहे थे तभी तेज रफ्तार से आ रही एमएसआरटीसी बस ने उनके वाहन को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन की रेप्युटेशन को बनाए रखने वाली महान लीडरशिप चली गई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीनियर लीडर शिवराज पाटिल-चाकुरकर को इमोशनल ट्रिब्यूट दिया

दिव्यांश
मुंबई(संवाददाता)

सीनियर लीडर शिवराज पाटिल-चाकुरकर को हमेशा एक ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने महाराष्ट्र की पॉलिटिकल फील्ड में शालीनता और सोफिस्टिकेशन की रेप्युटेशन को बनाए रखा और इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व लोकसभा स्पीकर, यूनियन मिनिस्टर शिवराज पाटिल-चाकुरकर को इमोशनल ट्रिब्यूट दिया है। उनके जाने से, हमने पॉलिटिक्स और सोशल वर्क में एक ऐसा गाइड करने वाला लीडर खो दिया है, मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने अपना दुख जताया है।

अपने शोक संदेश में, मुख्यमंत्री ने कहा, चाकुरकर ने लातूर के मेयर के तौर पर पॉलिटिक्स में एंट्री की। उन्होंने डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, पार्लियामेंट की अलग-अलग कमेटियों के मेंबर, और बाद में सेंटर में अलग-अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर और लोकसभा के स्पीकर, और पंजाब के गवर्नर के तौर पर काम किया। वे सात बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संसद से जुड़ी कई नई पहलों को मज़बूती दी। चाकुरकर ने एक वकील के तौर पर संविधान का गहरा अध्ययन किया था। इसके ज़रिए उन्होंने लोकसभा में संसदीय काम करने के तरीके को और मज़बूत किया। एक सिद्धांतवादी, विद्वान और पक्के नेता के तौर पर देश की राजनीति में उनका सम्मान था। चाकुरकर के निधन से, हमने, महाराष्ट्र के बेटे ने, एक ऐसा सीनियर नेता खो दिया है जिसने राजनीति और समाज में तहज़ीब, नफ़ासत और लोकतंत्र में मज़बूत विश्वास बनाए रखा। चाकुरकर परिवार और उनके कार्यकर्ताओं पर इसका असर पड़ा है। हम उन सभी के दुख में शामिल हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें यह दुख सहने की ताकत दे और सीनियर नेता शिवराज पाटिल चाकुरकर को दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं अजमेर के बीच चलाएगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अजमेर में उर्स फेस्टिवल के लिए यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को समायोजित करने के लिए बांद्रा टर्मिनस एवं अजमेर स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09027/09028 बांद्रा टर्मिनस - अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल (04 फेरे)

ट्रेन संख्या 09027 बांद्रा टर्मिनस - अजमेर स्पेशल सोमवार और गुरुवार, 22 एवं 25 दिसंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 12:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:20 बजे अजमेर पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09028 अजमेर - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल मंगलवार और शुक्रवार, 23 एवं 26 दिसंबर, 2025 को अजमेर से 10:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, दहानू रोड, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर और नसीराबाद स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09027 की बुकिंग 14 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

महाराष्ट्र में माइक्रोसॉफ्ट का भारी निवेश, एआई हब, 45 हजार लोगों के लिए रोजगार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला से मुलाकात की और भारत के पहले एआई-संचालित प्लेटफॉर्म महाक्राइमओएस एआई का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों की जांच में तेजी लाना है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने फेसबुक पर लिखा कि महाराष्ट्र ने डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है। #AITourMumbai में सत्य नडेला से मिलकर बेहद खुशी हुई, जहां हमने महाक्राइमओएस एआई का अनावरण किया - भारत का पहला एआई-संचालित प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों की जांच में तेजी लाना है। 23 पुलिस स्टेशनों से 1100 तक विस्तार; नागपुर से राज्यव्यापी स्तर तक, महाराष्ट्र नागरिक सुरक्षा के लिए एआई-संचालित शासन को बढ़ावा दे रहा है! उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें भी साझा कीं।

राज्य सरकार के अनुसार, महाराष्ट्र साइबर अपराधों की जांच में तेजी लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित प्लेटफॉर्म से अपनी पुलिस को लैस करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। महाक्राइमओएस एआई नामक एआई-संचालित प्रणाली का अनावरण मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर में किया गया, जो भारत के डिजिटल पुलिसिंग प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। साइबरआई द्वारा महाराष्ट्र सरकार के विशेष प्रयोजन वाहन मार्वल और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर (आईडीसी) के सहयोग से विकसित महाक्राइमओएस एआई, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और ओपनएआई तकनीकों का उपयोग करके पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराधों को तेजी से ट्रैक करने और हल करने में मदद करता है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म पहले से ही नागपुर के 23 पुलिस स्टेशनों में चालू है और राज्य के सभी 1,100 पुलिस स्टेशनों में इसका विस्तार करने की योजना है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनहित के लिए नैतिक और जिम्मेदार एआई हमारा मूलमंत्र है। एआई में दक्षता में सुधार, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि और प्रत्येक नागरिक के लिए वास्तविक सुगम जीवन प्रदान करके परिवर्तन लाने की शक्ति है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारा सहयोग जटिल साइबर अपराध चुनौतियों को हल करने से शुरू हुआ, लेकिन इसकी क्षमता कहीं अधिक है। हम इस शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करके एक अधिक प्रभावी, नागरिक-केंद्रित राज्य का निर्माण करना चाहते हैं।

नर्सिंग डायरेक्टरेट के लिए हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जॉइंट मीटिंग होगी-पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश अबितकर

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नागपुर। नर्सिंग कैडर हेल्थ सर्विस की आत्मा है और नर्सिंग सर्विस को और बेहतर बनाया जाएगा। नर्सिंग पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश अबितकर ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में आधे घंटे की चर्चा के जवाब में बताया कि डायरेक्टरेट बनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जॉइंट मीटिंग होगी।

मेंबर उमा खापरे ने उम्मीद जताई कि इस बारे में मीटिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल स्पीकर की अध्यक्षता में होनी चाहिए। स्पीकर राम शिंदे ने हेल्थ डिपार्टमेंट को इस मीटिंग की अध्यक्षता करने का निर्देश दिया।

मेंबर विक्रम काले ने राज्य में नर्सिंग डायरेक्टरेट बनाने के बारे में लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश की गई आधे घंटे की चर्चा में हिस्सा लिया।

राज्य में, ग्रामीण इलाकों में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, शहरी इलाकों में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए मरीज़ों को मेडिकल सर्विस दी जा रही हैं। इसलिए, राज्य में नर्सिंग डायरेक्टरेट बनाने के बारे में स्ट्रेटेजिक फैसला लेने के लिए इन डिपार्टमेंट्स की एक जॉइंट मीटिंग होगी, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा। मिनिस्टर अबितकर ने यह भी कहा कि क्योंकि हेल्थ सर्विस में नर्सिंग सर्विस का बहुत महत्व है, इसलिए पब्लिक

हेल्थ डिपार्टमेंट ने नर्सिंग कैडर के बारे में एक अलग मीटिंग की है और इस कैडर के लिए एक अलग डायरेक्टर अपॉइंट करने का एक्शन भी चल रहा है।

छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास देश भर के स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कमिटेड है- राज्य मंत्री पंकज भोयर

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्य मंत्री पंकज भोयर ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में आधे घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को पूरे देश के स्टूडेंट्स तक पूरे सम्मान के साथ पहुंचाने के लिए कमिटेड है और इस पर और तेज़ी से काम किया जाएगा।

मेंबर सत्यजीत तांबे ने CBSE करिकुलम में छत्रपति शिवाजी महाराज पर कम इतिहास लिखे जाने पर आधे घंटे की चर्चा पेश की थी। मेंबर अमोल मिटकरी, जे.एम. अभ्यंकर ने चर्चा में हिस्सा लिया।

राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि वह CBSE करिकुलम में छत्रपति शिवाजी महाराज के शानदार इतिहास को शामिल करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और यह पक्का करने की अहमियत बताएंगे कि देश भर के लाखों स्टूडेंट्स को छत्रपति शिवाजी महाराज के काम का सही, गहराई से और प्रेरणा देने वाला इंट्रोडक्शन मिले।

पंकज भोयर ने कहा कि राज्य सरकार के फॉलो-अप की वजह से, CBSE करिकुलम में 'द राइज़ ऑफ़ मराठाज़' पर एक अलग चैप्टर शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के ज़रिए NCERT को एक डिटेल्ड प्रपोज़ल भेजा गया है। बताया गया है कि राज्य ने मांग की है कि महाराष्ट्र के इतिहास, भूगोल और खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज के काम पर और ज़्यादा जानकारी शामिल की जानी चाहिए।

राज्य के स्कूलों में 'शिवचरित्र रीडिंग' पहल के विचार को पॉज़िटिव बताते हुए, राज्य मंत्री भोयर ने यह भी कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से चर्चा करने के बाद इस पहल को लागू करने की कोशिश की जाएगी।

सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर आधारित कई स्कीमें लागू की हैं।

उन्होंने साफ़ किया कि सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना, छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि योजना, और छत्रपति शिवाजी महाराज रेवेन्यू समाधान शिविर जैसी स्कीमों के ज़रिए हर नागरिक को सरकारी सुविधाएँ देने के लिए कमिटेड है।

पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट, सड़क का काम और मेट्रो कॉरिडोर का काम चल रहा है- मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पुणे शहर और उसके आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए रिंग रोड समेत कई सड़क और मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। रिंग रोड के पूर्वी हिस्से का काम मई 2028 तक और पश्चिमी हिस्से का काम मई 2026 तक पूरा हो जाएगा। साथ ही, हड़पसर-लोनी कालभोर मेट्रो कॉरिडोर के काम की टेक्निकल फिजिबिलिटी की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी, मंत्री दादाजी भुसे ने बताया।

वे पुणे रिंग रोड और दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में सदस्य राहुल कुल के दिलचस्प सुझाव का जवाब देते हुए बोल रहे थे। सदस्य सुनील शेल्के और अभिजीत पाटिल ने इस चर्चा में हिस्सा लिया।

मंत्री भुसे ने कहा कि पुणे के ग्रामीण इलाकों में ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए शईंऊ और शएछ्ऊ के ज़रिए रिंग रोड, दूसरी सड़कों के डेवलपमेंट और हड़पसर-लोनी कालभोर मेट्रो कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।

पुणे रिंग रोड का काम शुरू; ईस्ट-वेस्ट फेज़ पर काम चल रहा है

प्रशासन ने पुणे रिंग रोड समेत ज़िले में

ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। रिंग रोड ईस्ट के 12 में से नौ पैकेज पर काम तेज़ी से चल रहा है और बाकी तीन पैकेज एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी के प्रोसेस में हैं। इन तीनों पैकेज के लिए टेंडर प्रोसेस मई 2026 से पहले पूरा हो जाएगा। साथ ही, असल काम अक्टूबर 2026 से शुरू होगा।

मंत्री भुसे ने कहा कि रिंग रोड वेस्ट के सभी पांच पैकेज पर काम चल रहा है और प्रोजेक्ट के पूरा होने की तारीख पश्चिम में मई 2027 और पूर्व में मई 2028 तय की गई है।

सड़क प्रोजेक्ट्स में तेज़ी

MSIDC पुणे ज़िले में ज़रूरी सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए तेज़ी से काम कर रहा है। हड़पसर - यावत रोड प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रोसेस चल रहा है। कैबिनेट ने पुणे - शिरूर सिक्स-लेन रोड को मंज़ूरी दे दी है और टेंडर मंज़ूरी का प्रोसेस चल रहा है। शिरूर - छत्रपति संभाजीनगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण पूरा हो गया है। इस मौके पर मिनिस्टर भुसे ने बताया कि तलेगांव - चाकन - शिकरापुर एलिवेटेड रोड के लिए टेंडर प्रोसेस चल रहा है।

हडपसर - लोणी कालभोर मेट्रो कॉरिडोर में तेज़ी

महामेट्रो ने 11.8 km लंबी मेट्रो को मंज़ूरी दे दी है और एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर क्रॉसिंग जैसे टेक्निकल मामलों के लिए अधिकारियों की एक अलग मीटिंग करने के निर्देश दिए गए हैं और फ़ीज़िबिलिटी स्टडी के बाद आगे के फ़ैसले लिए जाएँगे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन कामों पर सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके प्रोजेक्ट की परमिशन, ज़मीन अधिग्रहण और काम की रफ़्तार का समय-समय पर रिव्यू करने का आदेश दिया है। मिनिस्टर भुसे ने कहा कि ट्रैफ़िक को आसान बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर अजित पवार ने बताया कि सोलापुर-पुणे रोड के बारे में एक मीटिंग हुई थी और यह काम किया जाएगा।

शिवराज पाटिल चाकुरकर के निधन से एक सभ्य, मेहनती और मेहनती इंसान खो गया है- डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार

डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने शिवराज पाटिल चाकुरकर को श्रद्धांजलि दी

नागपुर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने अपनी संवेदनाएं जताते हुए कहा है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर, लोकसभा के पूर्व स्पीकर और देश के पूर्व होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल चाकुरकर के निधन से हमने देश की पॉलिटिक्स में एक सभ्य, मेहनती और मेहनती इंसान खो दिया है।

अपने शोक संदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा है कि शिवराज पाटिल चाकुरकर ने पब्लिक सर्विस का एक नया आदर्श बनाया था। वे सादगी और नैतिक मूल्यों के प्रतीक थे। अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में लोकसभा स्पीकर, यूनियन मिनिस्टर, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पंजाब गवर्नर जैसे अलग-अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा पॉलिटिक्स की नैतिकता को बनाए रखा। लोकसभा स्पीकर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने लोकसभा का मॉडर्नाइज़ेशन, कंप्यूटराइज़ेशन, पार्लियामेंट की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट, नई लाइब्रेरी बिल्डिंग जैसे कामों को तेज़ किया। उनके कार्यकाल में आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवॉर्ड शुरू किया गया था। उन्होंने भारतीय संविधान की गहरी पढ़ाई की थी। डेमोक्रेसी को मज़बूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने इन शब्दों में शिवराज पाटिल चाकुरकर को श्रद्धांजलि दी है।

राज्य में 10 उमेद मॉल बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध- ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोर

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

कैबिनेट ने राज्य में महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को एक परमानेंट मार्केट देने के लिए 'उमेद मॉल' के बड़े कॉन्सेप्ट को मंज़ूरी दे दी है। ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोर ने बताया कि पहले फेज में राज्य के 10 जिलों में उमेद मॉल बनाने का टारगेट है, जिसके लिए सरकार ने ?200 करोड़ का प्रोविजन किया है।

जब विधानसभा मेंबर राणा जगजीतसिंह पाटिल, सुनील प्रभु, योगेश सागर, संजय कुटे, नारायण कुचे, सुधीर मुनगंटीवार, सत्यजीत देशमुख, मुरजी पटेल, समीर मेघे ने क्वेश्चन आवर के दौरान उमेद मॉल के बारे में सवाल पूछे, तो मंत्री श्री गोर ने जानकारी दी।

महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को बहुत सपोर्ट दिया जा रहा है और मंत्री श्री. गोरे ने कहा कि राज्य में 6,53,192 सेल्फ-हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, और उन्हें अब तक ?872 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बांटा जा चुका है। जबकि 3,70,350 ग्रुप को ?222 करोड़ का कम्युनिटी फंड दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की रोजी-रोटी के लिए छोटे लेवल पर बिजनेस काफी बढ़ा है क्योंकि उन्हें बैंकों से भी बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल मदद मिल रही है।

ग्रामीण इलाकों में महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को मार्केट देने के लिए पूरे राज्य में 'महालक्ष्मी सरस', डिस्ट्रिक्ट और मिनी सरस जैसी एग्जीबिशन लगाई जाती हैं। हालांकि, क्योंकि ये सेंटर टेम्परारी हैं, इसलिए महिलाओं के लिए 12 महीने के लिए एक परमानेंट मार्केट 'उमेद मॉल' (डिस्ट्रिक्ट सेल्स सेंटर) बनाने का फैसला किया गया है, उन्होंने कहा। मंत्री श्री गोरे ने कहा कि हर जिले में कम से कम 20,000 sq. ft. का मॉल बनाने का प्लान है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सही जगहों को चुनने की प्रोसेस में हैं।

सरकार यह पक्का करने की कोशिश कर रही है कि कुपोषण से एक भी बच्चे की मौत न हो- महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे

नागपुर।राज्य में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या 2019-20 में 246 से घटकर 2025-26 में 97 हो गई है। सरकार यह पक्का करने की कोशिश कर रही है कि कुपोषण से एक भी बच्चे की मौत न हो और महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, आदिवासी विकास जैसे संबंधित विभागों की एक टीम बनाई जाएगी, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने विधान परिषद में आधे घंटे की बहस के जवाब में कहा।

सदस्य उमा खापरे ने कुपोषण से बच्चों की मौत के मुद्दे पर चर्चा पेश की।

सदस्य संजय खोपड़े, प्रवीण दारकेकर, चित्रा वाघ ने इस चर्चा में भाग लिया।

मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का अनुपात 2024 के 0.79 प्रतिशत से घटकर 2025 में 0.41 प्रतिशत हो गया है। मुख्यमंत्री के 100-दिन के प्रोग्राम में भी कुपोषण खत्म करने को खास प्राथमिकता दी गई है।

इस चर्चा का जवाब देते हुए राज्य मंत्री मेघना साकोरे बोर्डिकर ने कहा, सरकार यह पक्का करने के लिए कई कोशिशें कर रही है कि मांएं स्वस्थ हों और बच्चे मजबूत पैदा हों। दूर-दराज के इलाकों में कई कदम उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। टॉयलेट बेहतर किए जा रहे हैं। काउंसलिंग की जा रही है ताकि सभी डिलीवरी अस्पतालों में हो सकें। ICDS के ज़रिए राज्य में 42,602 गर्भवती मांओं और बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है। हालांकि, उन्होंने बताया कि राज्य में बच्चों की मौत सिर्फ कुपोषण की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि इसके कई कारण हैं।

लोहेगांव समेत 11 नए गांवों का डेवलपमेंट प्लान फाइनल स्टेज में- मंत्री उदय सामंत

नागपुर। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोहेगांव समेत 11 नए गांवों को शामिल करने के लिए प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान (DP) का फाइनल प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है, और कानून के मुताबिक सभी स्टेज पूरे होने के बाद ही फाइनल DP की घोषणा की जाएगी, शहरी विकास मंत्री उदय सामंत ने बताया। विधानसभा में सदस्य बापूसाहेब पठारे के उठाए गए दिलचस्प सुझाव का जवाब देते हुए, मंत्री सामंत ने कहा कि संबंधित DP का ड्राफ्ट 16 अक्टूबर, 2025 को घोषित किया गया है। आपत्तियां और सुझाव फाइल करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर, 2025 है और सुनवाई की प्रक्रिया 60 दिन का समय पूरा होने के बाद होगी।

एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन प्रिवेंशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के नियमों का उल्लंघन

18 डेवलपर्स पर काम रोकने की कार्रवाई

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर कंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। इन कामों से होने वाले नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और ब्लास्टिंग के बारे में मिली शिकायतों के बाद, माननीय हाई कोर्ट, मुंबई ने माननीय हाई कोर्ट के 11/12/2023 को दिए गए आदेश के अनुसार, अपनी (सुओ मोटो) पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 3/2023 फाइल की है, और एयर पॉल्यूशन कम करने के आदेश जारी किए हैं। इस बारे में, म्युनिसिपल कमिश्नर डॉ. कैलाश शिंदे की मंज़ूरी से, 1 अगस्त 2024 को एक सर्कुलर जारी किया गया है।

इसके अनुसार, कमिश्नर के गाइडेंस में, 06 नवंबर 2025 को नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के सभी डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स के साथ-साथ सभी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नरों और डिपार्टमेंटल अधिकारियों के साथ एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें नॉइज़ और एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए पब्लिश स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करने के निर्देश दिए गए थे। इस मीटिंग में, असिस्टेंट डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग श्री सोमनाथ केकन ने सभी डेवलपर्स को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में डिटेल में जानकारी दी और उन्हें इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। यह साफ तौर पर बताया गया कि जो डेवलपर्स इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और अगर इस बारे में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो इन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्शन रोकने के ऑर्डर जारी किए जाएंगे।

इस सर्दी के मौसम में हवा में बढ़ी धूल और गंदगी को देखते हुए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर प्रदूषण रोकने के नियमों का पालन पक्का करने के लिए कई कदम उठाए गए और साइट्स पर जाकर उनका इंस्पेक्शन करने के निर्देश दिए गए। इसके मुताबिक, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट के हिसाब से इंजीनियरों की टीमें बनाईं ताकि यह पक्का किया जा सके कि असल साइट पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ठीक से लागू हो रहे हैं। जब इन इंजीनियरों ने बन रहे प्रोजेक्ट्स की साइट्स पर जाकर उनका इंस्पेक्शन किया, तो पाया गया कि कुल 85 प्रोजेक्ट साइट्स पर इन प्रोसीजर का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा था।

इसके अनुसार, 26 नवंबर 2025 के लेटर के ज़रिए, इन 85 प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स को एक्ट के नियमों के अनुसार पेनल्टी लेने और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत मामलों को जल्दी पूरा करने और अगले 7 दिनों में अपनी सफाई देने के बारे में बताया गया। नहीं तो, यह बताया गया कि उनके प्लॉट पर दी गई कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए स्टॉप वर्क ऑर्डर जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

मध्य रेल पर रविवार को मेगा ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल, मुंबई मंडल रविवार, दिनांक 14.12.2025 को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए अपने उपनगरीय खंडों पर मेगा ब्लॉक परिचालित करेगा। इसका विवरण इस प्रकार है:

मेन लाइन:

माटुंगा-मुलुंड अप और डाउन फास्ट लाइन 11.05 बजे से 15.45 बजे तक। सीएसएमटी मुंबई से 10.36 बजे से 15.10 बजे तक चलने वाली डाउन फास्ट लाइन सेवाएं माटुंगा स्टेशन पर डाउन स्लो लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी और माटुंगा और मुलुंड स्टेशनों के बीच अपने निर्धारित ठहरावों के अनुसार रुकेंगी और अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी। ठाणे से आगे जाने वाली फास्ट ट्रेनों को मुलुंड स्टेशन पर डाउन फास्ट लाइन पर पुनः डायवर्ट किया जाएगा।

ठाणे से सुबह 11:03 बजे से दोपहर 15:38 बजे तक चलने वाली अप फास्ट लाइन की सेवाएं मुलुंड स्टेशन पर अप स्लो लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी। मुलुंड और माटुंगा स्टेशनों के बीच अपने ठहरावों के अनुसार रुकेंगी और पुनः माटुंगा स्टेशन पर अप फास्ट लाइन पर वापस डायवर्ट की जाएंगी तथा अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी

ट्रांस-हार्बर लाइन:

ठाणे और वाशी/नेरुल स्टेशनों के बीच अप और डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन पर सुबह 11:10 बजे से शाम 16:10 बजे तक

इस अवधि के दौरान वाशी/नेरुल और ठाणे स्टेशनों के बीच अप और डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी।

ठाणे से वाशी/नेरुल/पनवेल जाने वाली डाउन लाइन की सेवाएं सुबह 10:35 बजे से शाम 16:07 बजे तक और पनवेल/नेरुल/वाशी से ठाणे जाने वाली अप लाइन की सेवाएं सुबह 10:25 बजे से शाम 16:09 बजे तक रद्द रहेंगी।

ये रखरखाव मेगा ब्लॉक बुनियादी ढाँचे के रखरखाव और संरक्षा के लिए आवश्यक हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इससे होने वाली असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन को सहयोग करें।

सम्पादकीय

संतुलन का तकाजा! ट्रेड डील पर समानता आधारित समझौते की अपेक्षा

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के संबंध में कुछ सकारात्मक संकेत सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि क्या इस बातचीत में परस्पर समानता पर आधारित हित सुनिश्चित होने और एक संतुलित समझौते की राह साफ होगी। गौरतलब है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश के तहत अमेरिकी दल वार्ता के लिए भारत में है। इसी बीच अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर ने कहा कि व्यापार समझौते के संदर्भ में भारत की ओर से 'अब तक के सबसे अच्छे प्रस्ताव' मिले हैं।

माना जा रहा है कि इस बयान का उद्देश्य अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए शुल्क से उपजे गतिरोध को दूर करने की कोशिश करना है। इसकी वजह यह है कि एकतरफा और मनमानी शुल्क नीति के जरिए दबाव बनाने की कोशिश के समांतर व्यापार समझौते के लिए वार्ता में सकारात्मक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर व्यापार वार्ता में गतिरोध की एक मुख्य वजह ही अमेरिका की नई शुल्क नीति रही है। इसलिए यह देखने की बात होगी कि इस मसले पर अमेरिका के रुख में कितना बदलाव आ पाता है।

दरअसल, व्यापार वार्ता के सकारात्मक दिशा में बढ़ने के मद्देनजर जारी कोशिशों के तहत ही भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते का सवाल अब एक मुख्य बिंदु है। इससे पहले अमेरिका का रवैया आमतौर पर यही सामने आ रहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हो, लेकिन उसकी शर्तों पर। इसी क्रम में उसने शुल्क लगाने के फैसले को दबाव के एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया। उसकी यह मंशा अधूरी रही, क्योंकि नुकसान की तमाम आशंकाओं के बावजूद भारत ने इस मसले पर अपना स्वतंत्र रुख बरकरार रखा।

इसके बावजूद, यह हकीकत है कि अमेरिका के शुल्क लगाने से उपजी परिस्थिति अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य पर विपरीत प्रभाव तो डाल ही रही थी। भारत के सामने भी कुछ चुनौतियां खड़ी होने की आशंका बनी रहीं। इसलिए भारत ने थोड़ा व्यावहारिक नीति पर आगे बढ़ते हुए अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई है, लेकिन इसके पीछे समानता आधारित समझौते की अपेक्षा भी है।

अमेरिकी शुल्कों में कटौती, भारतीय उत्पादों के अमेरिकी बाजार में आसान प्रवेश, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी, दवा और सेमीकंडक्टर उद्योग आदि व्यापार वार्ता के मुख्य मुद्दों में शामिल हो सकते हैं। मुश्किल वहां आ सकती है, जिसमें अमेरिका भारत से कृषि, डेयरी और डिजिटल नीति के संदर्भ में कई महत्त्वपूर्ण रियायतों पर जोर दे रहा है।

जाहिर है, भारत के लिए थोड़ा सजग रहने का वक्त है, क्योंकि अमेरिका के साथ वार्ता में खासतौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े कई सवाल उभरे हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने यहां के किसानों की आमदनी कम होने के लिए कुछ अन्य देशों सहित भारत के चावल की बिक्री को जिम्मेदार ठहराया।

दूसरी ओर, अगर अमेरिका अपना मक्का, गेहूं, कपास और सोयाबीन जैसे उत्पाद भारतीय बाजारों में निर्यात करता है, तो इससे भारत के छोटे किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसी तरह, किसी समझौते की स्थिति में भारत को कृषि और जेनेटिकली माडिफाइड, यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर भी छूट देने के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है।

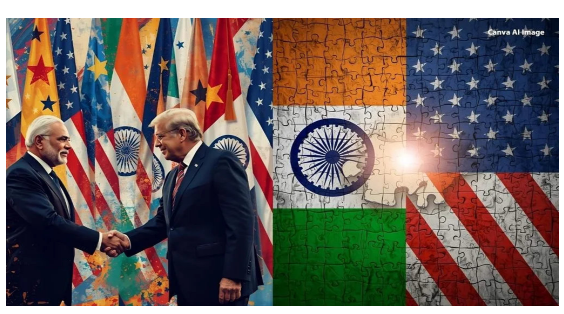

दबाव के दायरे में पिसता बचपन, जीवन समाप्त करने की दिख रही प्रवृत्ति

देश भर में बच्चों से लेकर युवाओं तक के जीवन पर पढ़ाई का दबाव और अन्य तरह के अवसाद भारी पड़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं ने यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे शिक्षण संस्थानों में कैसा माहौल है और वहां किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए अभिभावकों, समाज और सरकार की ओर से सामूहिक रूप से व्यापक स्तर पर प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं?

हम ऐसा सुनते और पढ़ते आए हैं कि शिक्षा मनुष्य को शोषण, दमन, हिंसा और असमानता से लड़ना सिखाती है, उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। स्कूल बच्चों को समाज का सभ्य नागरिक बनना सिखाते हैं, उन्हें जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। ऐसे में सवाल है कि आज बच्चों को किस तरह से शिक्षित किया जा रहा है कि उनके भीतर जीवन शुरू होने से पहले ही उसे समाप्त करने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है!

कुछ समय पहले दो बड़ी घटनाएं हुई, जिन्होंने पूरे समाज को झकझोर दिया। राजस्थान में जयपुर के एक स्कूल की चौथी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने इमारत से कूद कर आत्महत्या कर ली। इस घटना में पीड़ित छात्रा को सहपाठियों द्वारा तंग करने और शिक्षकों की ओर से उसकी शिकायतों को अनदेखा करने के आरोप लगे। दूसरी घटना में दिल्ली के एक स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर खुदकुशी कर ली। इस मामले में शिक्षकों पर संबंधित छात्र को उपेक्षित-प्रताड़ित करने के आरोप लगे। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कभी शिक्षा के मंदिर कहलाने वाले विद्यालय अब शिक्षा के बाजार बन गए हैं, जहां शिक्षा को ऐसे बेचा जाता है कि उससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। आज के दौर में शिक्षा के व्यापार को सबसे अधिक फायदे वाला कारोबार माना जाता है। इस कारण अब हरेक नागरिक की शिक्षा तक समान पहुंच मुमकिन नहीं रह गई है।

देखा जाए तो बाजार ने शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य, दोनों बदल डाले हैं। पहले विद्यार्थी तय करता था कि उसे किस तरह के विषय पढ़ने चाहिए, उसकी रुचि किसमें है। मगर अब बाजार तय करता है कि उसे कौन-सा विषय पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और कुशलता का निर्धारण भी बाजार ही करता है। यहां तक कि विद्यार्थी अपनी जिंदगी या करिअर में सफल है या असफल, यह भी बाजार ही तय करता है। इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य अब संवेदनहीन, भावहीन और गैर-तार्किक मशीन में तब्दील हो चुका है, जिसका 'रिमोट' कुछ ताकतवर लोगों के हाथों में है। ऐसे में कई बार लोगों के मन में यह विचार भी आ सकता है कि इससे तो पहले का समाज ही अच्छा था, जहां लोग निरक्षर या कम पढ़े-लिखे थे, लेकिन स्वार्थ, लालच, धोखा, अविश्वास जैसे शब्दों से परिचित ही नहीं थे या उनसे दूर थे!

इतनी कम उम्र के बच्चे, जिन्हें सही से जीवन का अर्थ भी नहीं पता, संघर्षों और चुनौतियों ने जिन्हें अभी छुआ भी नहीं है, वे

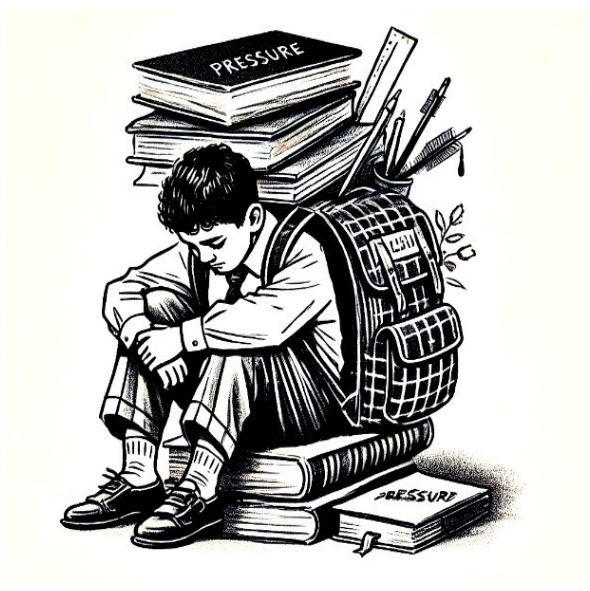

अचानक से जीवन को समाप्त करने जैसे निर्णय तक पहुंच रहे हैं तो आखिर इसकी क्या वजह है? समस्या कहां हैं- परिवार में, शिक्षण संस्थानों में, नीति निर्माताओं में, प्रशासनिक व्यवस्था में, पाठ्यक्रमों में या फिर पूरा समाज ही अव्यवस्थित हो गया है। शिक्षा का उद्देश्य तो बच्चों में सही-गलत एवं नैतिक-अनैतिक के बीच निर्णय लेना सिखाना है, कल्याणकारी समाज की नींव को मजबूत करने की भावना पैदा करना है, आलोचनात्मक चेतना विकसित करना है, मगर धरातल पर ऐसा हो नहीं रहा है। रही सही कसर तकनीक के विकास ने पूरी कर दी है।

इंटरनेट की दुनिया में सोशल मीडिया ने सूचना के प्रयास को भले ही आसान कर दिया है, लेकिन इससे बच्चों की कल्पनाशक्ति, सृजनात्मकता और कुछ अलग सोचने की क्षमता हाशिये पर आ गई है। समय और उम्र से पहले ही बच्चे वह सब देखने और जानने लगे हैं, जिसकी जानकारी होना उनके लिए अभी जरूरी नहीं है। साथ ही इस भौतिकतावादी समाज में अभिभावक भी अपने बच्चों को 'स्मार्ट' बनाने की जल्दी में जिंदगी की संवेदना और अपने दायित्व को भूलते जा रहे हैं।

अब परिवारों में बच्चों की संख्या भले ही एक या दो ही रहने लगी है, लेकिन अभिभावकों के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं है। इस कारण धीरे-धीरे बच्चे भी परिवार के स्थान पर स्मार्टफोन या सोशल मीडिया के साथ ज्यादा समय बिताने लगे हैं। ऐसे में बच्चों से यह अपेक्षा करना कि वे संस्कृति और समाज के साथ समायोजन करेंगे, संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना सीखेंगे, बहुत दूर की कौड़ी है। बच्चों को एक उम्र तक डिजिटल दुनिया से दूर रखने के लिए कई देशों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं, ताकि तकनीक के दुष्प्रभावों से भावी पीढ़ी को बचाया जा सके। दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चीन, इटली और हंगरी जैसे देशों में छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करने और डिजिटल दुनिया की लत को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

प्राथमिक समाजीकरण जो पहले परिवार का दायित्व था, वह अब डिजिटल मीडिया करने लगा है। इसलिए अब इनके द्वारा उत्पन्न विचारों और सूचनाओं को हम बिना संदेह के विश्वसनीय और प्रामाणिक मानने लगे हैं। नतीजतन, बच्चे 'बंधक मस्तिष्क' और 'सीमित व्यक्तित्व' वाले बनते जा रहे हैं। मशहूर शिक्षाविद नील पोस्टमैन का कहना है कि आज की पीढ़ी निरर्थक विचारों से भरी और नकलची है, उसके पास जुमले हैं, मगर विचारधारात्मक चिंतन नहीं है। यह अलगाव का चरम स्तर है और ऐसे में समाज के विकास की दिशा क्या होगी, यह कहना मुश्किल है। आज की पीढ़ी के बच्चों ने अपने बचपन को जिया ही नहीं, उनकी मासूमियत जल्दी परिपक्वता में बदल रही है, तकनीक एवं डिजिटल मीडिया ने उम्र एवं समय से पहले ही इनका बचपन छीन लिया है।

राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में विद्यार्थी आत्महत्या की दर प्रतिदिन करीब 38 है, जो पिछले बारह वर्षों में लगभग पैंसठ फीसद बढ़ी है। वर्ष 2023 में मृतक विद्यार्थियों-परीक्षार्थियों की संख्या 13, 892 बताई गई है। ये तथ्य बहुत चौंकाने वाले हैं।

यह समस्या किसी एक की नहीं है, बल्कि परिवार, समाज, शिक्षण संस्थान और सरकार सभी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। केवल नीतियां बनाने से अगर काम चल सकता, तो विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाओं को कब का रोक लिया गया जाता। विचारणीय विषय यह है कि छोटी-सी उम्र में बच्चे अगर आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं, तो सोचिए कि उस समय उनकी मानसिक हालत कैसी रही होगी और वे किस दर्द से गुजर रहे होंगे।

कहा जाता है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे दुनिया को बदला जा सकता है, मगर दुनिया इस तरह बदलेगी, संभवतः ऐसी कल्पना किसी ने कभी भी नहीं की होगी। यह सच है कि जब तक कोई पीड़ा असहनीय नहीं होती, तब तक इंसान हिम्मत नहीं हारता और अगर हमारे बच्चे हिम्मत हारने लगे हैं, तो हम सबको मिलकर इसके कारण और समाधान तलाशने होंगे।

शिक्षा और संस्कृति, नई शिक्षा नीति केवल पाठ्यक्रम निर्धारण का केंद्र बनकर रह गई

नई शिक्षा नीति, 2020 को स्वतंत्र भारत की तीसरी प्रमुख शिक्षा नीति के रूप में देखा जाता है। नीति दस्तावेज में 'भारतीयता' की भावना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण और स्थानीय कला और संस्कृति से जोड़कर अधिगम की बात की गई है। शिक्षा के जमीनी ढांचे में विशेषकर राज्यों के स्तर पर इसका ठोस क्रियान्वयन अभी भी कई अड़चनों से घिरा हुआ है।

दरअसल, नई शिक्षा नीति केवल पाठ्यक्रम निर्धारण का केंद्र बनकर रह गई है, जबकि हमारी शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति और लोक संस्कृति के संवर्धन को आगे बढ़ाने वाली भी होनी चाहिए। पांच साल बीत जाने के बाद अभी तक न तो एकरूपता का पाठ्यक्रम निर्धारित हो पाया है और न ही भाषाई स्तर पर कोई प्रगति दिखाई दे रही है। इसके बिना राज्यों के लिए इसको आगे समझना मुश्किल लग रहा है।

भारत के दर्शन में 'सत्यं, शिवं, सुंदरम' की अवधारणा शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्यों को विकसित करने का आधार प्रदान करती है। नई शिक्षा नीति में भारतीय दर्शन और लोक परंपराओं को पाठ्यक्रम से जोड़ने की बात कही गई है, लेकिन उसका अनुपालन अभी संस्थागत रूप से दृश्यमान नहीं हुआ है। अगर विद्यार्थियों को अपनी परंपराओं और जन संस्कृति की समझ छोटे स्तर से ही दी जाए, तो भविष्य में भारतीय समाज एक जागरूक, सांस्कृतिक और स्वाभिमानी व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है।

संस्कृति का अर्थ केवल नृत्य, संगीत या चित्रकला नहीं है, बल्कि यह समाज के व्यवहार, भाषा, उत्सव, पहनावे और जीवन दृष्टि में प्रकट होती है। शिक्षा अगर केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का साधन बन जाए, तो वह अधूरी है। नई नीति को आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करने के बीच संतुलन बनाना था।

देश के अलग-अलग राज्यों में विभिन्न कलाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां, परंपराएं, भाषाई अभिव्यक्ति, कलाकृतियां, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर आदि परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। उसकी जानकारी नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम और भारतीय दर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को नियमित रूप से होनी चाहिए। भारत में खूबसूरत हस्तशिल्प, हाथ से बनी कला और संस्कृति का संवर्धन आम लोगों के बीच है, लेकिन समाज और राज्यों में अलग-अलग रूप से सामाजिक कल्याण के लिए, सांस्कृतिक जागरूकता का अपना बड़ा महत्त्व रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका उल्लेख तो किया गया है, पर पांच साल के बाद भी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया है। विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग शिक्षा प्राप्त करके अपने व्यापार या नौकरी पेशे में आ जाएगा, तब वह भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों से अछूता ही रहेगा। यहां का इतिहास, कला, भाषा और परंपरा की भावना ज्ञान के विकास द्वारा ही सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान बनाता है।

हर राज्य में अपनी विशिष्ट कला-परंपराएं, लोकगीत, नृत्य रूप, हस्तशिल्प, चित्रकला और भाषाई शैलियां विद्यमान हैं, जो भारतीय पहचान को पोषित करती हैं। नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा अवसर यह था कि इन क्षेत्रीय और लोककलाओं को शिक्षा के मुख्यधारा पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों में अपने समाज, संस्कृति और परंपरा के प्रति गर्व और अपनापन विकसित हो।

अफसोस की बात है कि यह विचार अभी तक दस्तावेजों में सीमित है। नीति में जिन पहलों का उल्लेख है, वे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ठोस विषय संरचना के रूप में विकसित नहीं हो पाई हैं। नई नीति के अंतर्गत बाल्यावस्था से लेकर उच्च शिक्षा तक, विद्यार्थियों के मातृभाषा में अध्ययन की सिफारिश की गई है। यह सैद्धांतिक रूप से भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास है।

संस्कृति हमारी विरासत और भाषा की संरचना से तय होती है। कला-सांस्कृतिक पहचान जागरूकता को समर्थ करता है, समाज को उन्नत करने के अलावा सृजनात्मक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। भारतीय कलाएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से आरंभ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को प्रदान की जानी चाहिए।

नई शिक्षा नीति के एक अध्याय में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति की बात की गई है। पर यह बात केवल दस्तावेजों तक सीमित न रहे, तो हम भाषाओं के आधार पर कलाओं एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। वे भारतीय भाषाएं भी, जो आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं हैं, उनके माध्यम से शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता शिक्षा नीति में होनी चाहिए।

वर्तमान समय में जब वैश्वीकरण और पश्चिमी शिक्षा माडल का प्रभाव गहराई तक पहुंच चुका है, तब भारतीय शिक्षा नीति को केवल प्रतिस्पर्धात्मक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वावलंबन के केंद्र के रूप में कार्य करना होगा। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को धरातल पर प्राप्त करने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थान और समाज- तीनों का समन्वित प्रयास आवश्यक है।

शिक्षा तभी सार्थक होगी, जब वह व्यक्ति को केवल रोजगार योग्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, रचनात्मक और सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण नागरिक के रूप में विकसित करे। इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति एक नए भारत के निर्माण का दस्तावेज बन सकती है, अगर इसे औपचारिक नीतिगत सीमाओं से निकालकर सांस्कृतिक-सामाजिक क्रियान्वयन के स्तर तक ले जाया जाए। भारत का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा, जब उसकी शिक्षा भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति और परंपरा से जुड़े मूल्यों के साथ आगे बढ़ेगी।

बंगाल में उभरते हिन्दू स्वरों में बदलते राजनीतिक समीकरण

पश्चिम बंगाल इन दिनों धार्मिक और राजनीतिक उफान का केंद्र बना हुआ है। बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक समूहों की सक्रियता के बीच हिन्दू धर्मगुरुओं एवं संगठनों की मोर्चाबंदी ने क्या हिंदू क्रांति का शंखनाद किया है? क्या यह आगामी विधानसभा चुनावों में हिंदू वोटों को एकत्र करने का नया एजेंडा है, या पश्चिम बंगाल में लगातार हिन्दुओं पर हो रहे हमलों, उनको कुचलने की कुचेष्टाओं एवं मुस्लिम तुष्टीकरण का माकुल जबाव है। बाबा बागेश्वर धाम-धीरेन्द्र शास्त्री सहित अनेक हिंदू धर्मगुरुओं के प्रवचनीय हस्तक्षेप, लाखों लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ और संतों की हुंकार से एक नई चेतना आकार लेती दिखाई दे रही है। यह उभार महज आस्था का नहीं, बल्कि पहचान, सुरक्षा और गौरव के भावों का उभार है।

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाना मानो एक सोए हुए राक्षस को जगाने जैसा है, क्योंकि यह केवल एक मस्जिद का प्रश्न नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द की कसौटी है। सदियों से चला आ रहा बाबरी विवाद भारत की सामाजिक चेतना पर गहरे जख्म छोड़ चुका है-जिसने राजनीति को उग्र बनाया, समुदायों को बाँटा और नफरत व हिंसा के बीज बोए। ऐसे समय में जब राष्ट्र विभिन्न संकटों से जूझ रहा है, इस विवाद को नए भूगोल में स्थानांतरित कर हवा देना सामाजिक सामंजस्य एवं राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हो सकता है। सद्भाव और शांति की बुनियाद पर खड़े भारत को ऐसे मुद्दों की आवश्यकता है जो एकता को मजबूत करें, न कि पुराने घाव कुरेदकर समाज में तनाव और अविश्वास पैदा करें। अतः आवश्यक है कि नेतृत्व इस संवेदनशील विषय को विवेक, संवाद और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर संभाले, ताकि भारत का बहुलतावादी चरित्र और साझा सभ्यता सुरक्षित रह सके।

निश्चित ही बाबरी मस्जिद विवाद को हवा देकर कुछ मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक वर्गों ने तनाव का वातावरण खड़ा किया है। इन दो समानांतर धाराओं की टकराहट ने बंगाल को विमर्श के केंद्र में ला दिया है कि क्या राज्य में हिंदू संगठित होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हिन्दू-विरोधी साजिशों एवं षडयंत्रों का अंत चाहते हैं? बंगाल परंपरा से बौद्धिक और सांस्कृतिक बहुलता का प्रदेश रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में हिंदू सामाजिक मानस में एक बदलाव दिख रहा है। 'गजवा हिंद' के प्रलापों के प्रतिकार में 'भगवा हिंद' का संकल्प उभर रहा है। पांच लाख से अधिक हिंदुओं द्वारा एक साथ गीता पाठ करना इसी उभार का संकेत है, जिसमें धर्म प्रदर्शन शक्ति और अस्मिता के रूप में सामने आता है। साध्वी ऋतंभरा के वक्तव्यों ने इस उभार को एक नया स्वर दिया है। उनका स्पष्ट कथन कि 'यह धरती प्रभु श्रीराम की है और श्रीराम की ही रहेगी' बंगाल सहित पूरे देश के हिंदू मानस में गूंज रहा है। यह कथन सिर्फ आस्था की घोषणा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अधिकार और आधिपत्य की अनुभूति का उद्घोष है। उनके भाषणों में उभरती चेतावनी है कि यदि हिंदू अपनी संस्कृति, परंपरा और मंदिरों की रक्षा के लिए नहीं उठे तो इतिहास स्वयं उनसे जवाब मांगेगा।

इस पृष्ठभूमि में बाबरी विवाद का पुनर्स्मरण राजनीति का साधन भी प्रतीत होता है। मुस्लिम संगठनों द्वारा इसकी मांगों को आगे बढ़ाना और नेताओं द्वारा इसे मुद्दा बनाना निश्चित ही सामाजिक भावना को चुनौती देता है। इसका प्रतिउत्तर धार्मिक मंचों से आया है, जहां प्रवचनों और सभाओं ने इसे हिंदू गौरव और अस्तित्व के प्रश्न के रूप में चित्रित किया है। ऐसे में यह कहना असंगत नहीं कि बंगाल की जमीन पर हिंदू पहचान की राजनीति तेजी से आकार ले रही है और हिन्दू धर्मगुरुओं के स्वर इसे वैचारिक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। उनका यह कथन कि 'राम का नाम अनंत है, पर पुरुषार्थ के बिना सिर्फ नाम से रामराज्य नहीं आएगा' एक सीधा संकेत है कि हिंदू समाज को संगठित, सक्रिय और आत्मनिर्भर होना होगा।

इस व्यापक परिदृश्य का मुख्य केंद्रबिंदु राजनीति है। क्या यह सब आगामी विधानसभा चुनावों का संकेत है? बंगाल की राजनीति लंबे समय से मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक भूमिका के आसपास घूमती रही है और ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज के भरोसे को अपने समर्थन की नींव बनाया है। परंतु यदि हिंदू मतदाता नए सांस्कृतिक उभार से प्रेरित होकर एकजुट होते हैं, तो पहली बार बंगाल की सत्ता-समीकरण बदल सकते हैं। भाजपा और संघ परिवार का प्रयास भी इसी दिशा में है कि धार्मिक सम्मेलनों को राजनीतिक चेतना का मंच बनाकर हिंदू अस्मिता को वैचारिक शक्ति प्रदान करना। भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और धार्मिक प्रवचनीय हस्तक्षेपों द्वारा बंगाल में हिंदू एकता और पहचान को जागृत करने की रणनीति अपनाई जा रही है। इस राजनीतिक परिपाटी में बाबा बागेश्वर जैसे मंच प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, धर्म-सम्मेलनों को राजनीतिक चेतना की पाठशाला में बदला जा रहा है। साध्वी ऋतंभरा का बंगाल में सक्रिय होना उसी रणनीति की कड़ी है, क्योंकि उनका सशक्त भाषण हिंदू भावनाओं को झकझोरता है। बंगाल जिसकी पहचान बौद्धिक विनम्रता, कविता, महात्म्य और सहिष्णुता से जुड़ी रही है, वह अब टकराव, ध्रुवीकरण और प्रतिआक्रामकता की ओर बढ़ता दिख रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में भावनात्मक आवेश बढ़ रहा है और नेताओं द्वारा इस माहौल को चुनावी लाभ के लिए साधने की त्रासद कोशिशें तेज हैं। यह परिस्थिति बंगाल के सामाजिक ताने-बाने के लिए चुनौतीपूर्ण है।

फिर भी एक बात निर्विवाद है- बंगाल में एक नई चेतना, एक नई आकांक्षा जन्म ले रही है। यह पूर्ण क्रांति है या क्रांति का शंखनाद, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा, परन्तु प्रारंभिक संकेत स्पष्ट हैं। हिंदू पहचान की राजनीति बंगाल में निर्णायक होती जा रही है, मुस्लिम वोट-बैंक की राजनीति पहली बार चुनौती में दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी की सत्ता को सांस्कृतिक विरोध का नया मोर्चा मिला है। अब यह समय बताएगा कि यह उभार सत्ता बदलता है या सामाजिक संवाद को बदलता है। लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति अब केवल विकास, योजनाओं और नेतृत्व की नहीं, बल्कि पहचान, इतिहास और प्रभुत्व की राजनीति बन चुकी है। यही कारण है कि धार्मिक मंचों की आवाज़ें चुनावी मैदान की धड़कन बन रही हैं। बंगाल अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ा है-जहाँ राम का दावा और राम की भूमि का संकल्प राजनीति, समाज और भविष्य तीनों को प्रभावित करने वाला तत्व बन चुका है।

न केवल मुस्लिम तुष्टिकरण बल्कि भ्रष्टाचार से लेकर मनमर्जी एवं तानाशाही का शासन चलाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रक्रिया बन गयी है। ममता वोट बैंक की राजनीति के लिये कानून की धज्जियां बार-बार उड़ाती रही है। ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों के वोट बैंक को बरकरार रखना रह गया है। मुद्दा चाहे रोहिंग्या मुसलामानों के अवैध प्रवेश का हो या फिर बांग्लादेशियों का या अब बाबरी मस्जिद का। इसके लिए ममता ने देश की एकता-अखंडता और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया है, कानून से खिलवाड़ जितना पश्चिमी बंगाल में हुआ है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राज्यों में हुआ हो। तृणमूल कांग्रेस हिन्दुओं को पश्चिम बंगाल में सेकेंड क्लास सिटिज़न एवं अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की उसकी सोच एवं नीति न केवल उनके घोषणा-पत्रों में बल्कि उनके बयानों में स्पष्ट झलकती रही है।

ममता ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, तृणमूल कांग्रेस का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक असंतुलन तथा रोष का कारण रहा है। बदले हुए राजनीतिक हालात इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनदेखी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है वह महज 'बागेश्वर बनाम बाबरी विवाद' नहीं है, यह सांस्कृतिक-धार्मिक पुनर्स्थापन की कोशिश बनाम राजनीतिक मुस्लिम केंद्रवाद की प्रतिस्पर्धा है। अभी के लिए, बंगाल की जमीन पर धर्म, राजनीति और पहचान का नया त्रिकोण उभर चुका है और वही आने वाले समय में बंगाल की राजनीतिक दिशा, सामाजिक संबंधों और सत्ता के समीकरणों को आकार देगा।

अपर जिलाधिकारी नगर ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से ससमय पूर्ण करायें जाने हेतु किया निर्देशित

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्र की अध्यक्षता में शुक्रवार को जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सहायक अभियन्ता, यू0पी0डा0 द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे का संरेखण जनपद मेरठ से लेकर प्रयागराज तक है। एक्सप्रेसवे का संरेखण कुल 12 जिलों से होकर गुजरता है। एक्सप्रेस वे की कुल लम्बाई 594 किमी0 है एवं परियोजना की लागत 36229.67 करोड़ है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में एक्सप्रेसवे की कुल लम्बाई 15.647 किमी0 है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 93.27 प्रतिशत है। ग्राम सभा पूरबनारा, सरांय मदन सिंह उर्फ चांटी, गिरधरपुर गोड़वा, सरांय हरीराम, सोरांव में कुछ काश्तकार संतुष्ट नहीं हैं। उपस्थित अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि उपजिलाधिकारी, सोरांव, प्रयागराज से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि अधिग्रण से सम्बंधित मामलों का निस्तारण करायें।

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड के सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 05 करोड़ से अधिक की 02 परियोजनाएं है, जिसकी भौतिक प्रगति 98 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जसरा बाई पास पर गड्ढे हैं, जिन्हें सुगम यातायात के दृष्टिगत मोटरेबुल किया जाय। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (पी0आई0यू0), प्रयागराज द्वारा इनर रिंग रोड का निर्माण कार्य 03 फेज में कार्य कराया जा रहा है। मार्ग के संरेखण में पड़ रहे कतिपय किसानों में अंश निर्धारण को लेकर आपसी विवाद है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अभियन्ता एवं पुलिस विभाग व उपजिलाधिकारी से आवश्यक संवाद के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान कराना सुनिश्चित करें।

सेतु निगम द्वारा जनपद प्रयागराज में शंकरगढ़ नारीबारी मार्ग पर उत्तर मध्य रेलवे के नैनी-मानिकपुर सेक्शन के किमी0 1313/0-1 पर रेल सम्पार सं0 415-ए/3ई पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसकी भौतिक प्रगति 63 प्रतिशत है। कार्य प्रगति पर है। बैठक में उपस्थित सेतु निगम के अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि कार्य को लक्षित समय में पूर्ण करायें तथा आगामी बैठक में रेलवे के स्टॉक होल्डर (जो सेतु का निर्माण करा रहें) उन्हें भी बैठक में बुलाया जाय।

भूमि अधिग्रहण के सम्बंध में कोई भी समस्या नहीं है। प्रान्तीय खण्ड द्वारा जनपद में 05 परियोजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। उपस्थित अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से प्राथमिकता के आधार पर लक्षित समय में पूर्ण करायें। नि0खं0-3 की 03 परियोजनाएं निर्माणाधीन है, घूरपुर प्रतापपुर मार्ग की भौतिक प्रगति 30 प्रतिशत है। निर्देशित किया गया कि परियोजना का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर कराते हुए कार्य को लक्षित समय में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अवशेष 02 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सहायक अभियन्ता, नि0खं0-4 (कु0मे0), लो0नि0वि0, प्रयागराज की 03 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी भौतिक प्रगति लगभग 80 प्रतिशत है। अपर जिलाधिकारी द्वारा कार्य को ससमय गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने प्रतिभाग किया:- पी0के राय, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, प्रयागराज, शशिकांत, अधिशासी अभियन्ता, नि0खं0-2(प्र0प0), लो0नि0वि0, प्रयागराज, नवीन कुमार शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, नि0खं0-3, लो0नि0वि0, प्रयागराज, मोहम्मद अरशद, सहायक अभियन्ता, प्रा0खं0, लो0नि0वि0, प्रयागराज, देवव्रत वैस, सहायक अभियन्ता, सेतु निगम, प्रयागराज, सी0के0डी0 द्विवेदी, सहायक अभियन्ता, नि0खं0-4(कु0मे0), लो0नि0वि0, प्रयागराज, अजय कुमार शुक्ला, सहायक अभियन्ता, नि0खं0-1, लो0नि0वि0, प्रयागराज, प्रदीप कुमार सिंह, अडानी ग्रुप गंगा एक्सप्रेसवे, एसोसियेट मैनेजर, प्रयागराज, अनिल पूनिया, ए0जी0एम0, गंगा एक्सप्रेसवे, प्रयागराज, नरेन्द्र शुक्ला, सहायक अभियन्ता, यू0पी0डा0, प्रयागराज, अजय सिंह, मैनेजर टेक्निकल, एनएचएआई, प्रयागराज, अभय सिंह, सहायक मैनेजर टेक्निकल, एनएचएआई, प्रयागराज, नीरज कुमार, सहायक अभियन्ता, मोर्थ, प्रयागराज, विशाल सेठ, सहायक अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, प्रयागराज एवं अन्य उपस्थित अधिकारीगण।

किसानों की मांग सहजीपुर-बड़नपुर माइनर में जल्द छोड़ा जाए पानी

मंत्र भारत संवाददाता

थरवई। क्षेत्र के सहजीपुर-बड़नपुर माइनर में नहर की सफाई हुए पंद्रह दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक नहर में पानी नहीं छोड़ा गया है। पानी न आने से सहजीपुर, बड़नपुर, नहरपुर, उदयचंद्रपुर, बनकेसरी, बनकट, मटियारा, पान की पुलिया, पंडिला, जैतवारडीह, बिगहिया समेत दर्जनों गांवों के किसान संकट में हैं।किसानों का कहना है कि आलू व गेहूं की फसल की सिंचाई की इस समय अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन नहर में पानी न पहुंचने से फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों ने नहर विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की है।

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत बालिकाओं एवं महिलाओं को किया जागरूक

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। पुलिस उपायुक्त यमुनानगर के निर्देशन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाये जा रहे अभियान 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत जोन यमुनानगर कमिश्नरेट प्रयागराज की मिशन शक्ति टीम द्वारा बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को थाना क्षेत्र के स्कूलों/कॉलेजों एवं सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिला सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण तथा केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे- सुकन्या समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, सामूहिक विवाह योजना, चिकित्सा संबंधी आयुष्मान योजना व हेल्पलाइन नंबर जैसे- वूमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन नंबर 101 आदि के बारे में जानकारी दी गई, इसके साथ ही साइबर फ्रॉड के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में जागरूक किया गया।

अपर जिलाधिकारी नगर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न बिना फिटनेस वाहन संचालन करने वाले स्कूली वाहनों पर कार्यवाही/नोटिस जारी करें

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्र की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जनपद में सड़क दुर्घटना माह नवम्बर, 2024 में 120 की तुलना में माह नवम्बर, 2025 में 136 सड़क दुर्घटना हुई। आगामी माह में सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत कमी लाये जानें के निर्देश दिये गये। प्रत्येक माह बैठक में निर्देशित किया जाता है कि अलोपीबाग फ्लाईओवर एवं पत्थर गिरजा घर के सामने (धरना स्थल) महाकुम्भ के दौरान रखे गये बोल्डर को हटाकर पैदल यात्रियों के लिए खोले जानें हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय, परन्तु लचर दृष्टिकोण अपनाये जानें के कारण समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है, इस सम्बंध में एसीपी0, ट्रैफिक व परिवहन विभाग एवं पीडीए व टीआई एक सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करायें।

एनएचएआई को निर्देशित किया गया कि एम्बुलेंस की उपलब्धता के आधार पर एक जूम के माध्यम से बैठक करते हुए यातायात पुलिस एवं मजिस्ट्रेट को जोड़ते हुए हर थानों एवं ब्लाकों को सूचना प्रसारित की जायेगी। जिससे कि कम से कम समय में समुचित इलाज घायलों/आहतों को दिया जा सके। परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि बिना फिटनेस वाहन संचालन करने वाले स्कूली वाहनों पर कार्यवाही/नोटिस जारी की जाय। परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि प्रस्तुत किये जा रहे आंकड़ों की शुद्धता की जांच शत-प्रतिशत कर ली जाय। आईटीएमएस द्वारा किये चालान को प्रतिमाह के चक्र के अनुसार एस0ओ0पी0 पर सूचना उपलब्ध करायी जाय। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि वृहद दुर्घटनाओं के दृष्टिगत शहर से जानें वाले विभिन्न राष्ट्रीय मार्गों के नजदीक ट्रामा सेंटरों व प्राइवेट तथा सरकारी हास्पिटल क्रियाशील रखा जाय। जिससे कि कम समय में समुचित इलाज घायलों/आहातों को दिया जा सके। सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाय। उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बैठक में उठाये गये बिन्दुओं पर शत-प्रतिशत अनुपालन आख्या ससमय उपलब्ध करायी जाय। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने प्रतिभाग किया:- पी0के राय, अधिशासी अभियन्ता/सचिव/

सदस्य, जिला सड़क सुरक्षा समिति, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, प्रयागराज, शैलेन्द्र सिंह, एसीपी ट्रैफिक, प्रयागराज, मोहम्मद अरशद, सहायक अभियन्ता/प्रतिनिधि सचिव/सदस्य, जिला सड़क सुरक्षा समिति, प्रयागराज, शशिकांत, अधिशासी अभियन्ता, नि0खं0-2(प्र0प0), लो0नि0वि0, प्रयागराज, नवीन कुमार शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, नि0खं0-3, लो0नि0वि0, प्रयागराज, अजय कुमार शुक्ला, सहायक अभियन्ता, नि0खं0-1, लो0नि0वि0, प्रयागराज, प्रदीप कुमार सिंह, अडानी ग्रुप गंगा एक्सप्रेसवे, एसोसियेट मैनेजर, प्रयागराज, अनिल पूनिया, ए0जी0एम0, गंगा एक्सप्रेसवे, प्रयागराज, नरेन्द्र शुक्ला, सहायक अभियन्ता, यू0पी0डा0, प्रयागराज, चन्द्रकांत धर द्विवेदी, सहायक अभियन्ता, नि0खं0-4(कु0मे0), लो0नि0वि0, प्रयागराज, डॉ0 बी0एस यादव, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, माध्यमिक शिक्षा, प्रयागराज, अजीत कुमार, अधिशासी अभियन्ता, नगर-निगम, प्रयागराज, आज़ाद राव, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रयागराज, डी0के0तिवारी, वरिष्ठ प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन, प्रयागराज, बसन्त लाल, उ0प्र0 परिवहन निगम, प्रयागराज, विशाल सेठ, सहायक अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, प्रयागराज, के0के0 सिंह, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बेलन कैनाल, प्रखण्ड, प्रयागराज, नरेन्द्र शुक्ला, सहायक अभियन्ता, यूपीडा, प्रयागराज, निकुंज तिवारी, सहायक अभियन्ता, पीआईयू मोर्थ, प्रयागराज, अजय सिंह, मैनेजर टेक्निकल, एनएचएआई, प्रयागराज, राम सागर, पी0टी0ओ0, परिवहन विभाग, प्रयागराज, डा0 रवीन्द्र, एम0ओ0, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज, रवीन्द्र त्रिपाठी, यातायात निरीक्षक, प्रयागराज, रघुनाथ द्विवेदी, उपाध्यक्ष टैम्पो टैक्सी यूनियन, प्रयागराज, विनोद चन्द्र दुबे, अध्यक्ष एवं रमाकान्त रावत, महामंत्री, टेम्पो टैक्सी यूनियन एवं अन्य उपस्थित अधिकारीगण।

पतजंलि नर्सरी स्कूल में उमंग, ऊर्जा लय का अनोखा संगम डांस मास्टर्स 7.0

डायरेक्टर, प्रधानाचार्या, अतिथियों ने बच्चों की प्रस्तुतियों की किया प्रशंसा

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। पतजंलि नर्सरी स्कूल के सभागार में शुक्रवार को आयोजित डांस मास्टर्स 7.0 ने रंग, ताल और उत्साह का ऐसा अद्भुत समागम प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों के मन को मंत्रमुग्ध कर दिया। केजी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों ने नृत्य के माध्यम से आनंद, संस्कृति और एकता का सुंदर संदेश दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत नन्हे बच्चों द्वारा प्रस्तुत 'केसरी के लाल' से हुई, जिसने पूरे वातावरण को भक्ति और पवित्रता से भर दिया। इसके बाद कक्षा 1 और 2 के छात्रों ने डायनामाइट के -पॉप डांस से मंच पर जोश और ऊर्जा का संचार किया। कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों ने भारतीय लोक नृत्यों की विविधता को अत्यंत मनोहारी और प्रभावशाली शैली में प्रस्तुत करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया।

कार्यक्रम की अन्य आकर्षक प्रस्तुतियां 'डेंजर – बॉलीवुड बीट्स', 'फॉर अ रीजन' और 'बिजुरिया पंजाबी पॉप'–ने दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। सबसे दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति रही 'उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराइ', जिसने पूरे सभागार में रंग और भावनाओं की अनूठी छटा बिखेर दी। 'जुंबा ता सजदा', 'छेड़खानियां', 'आवन-जावन हाउस फुटवर्क' और 'स्वीटी तेरा ड्रामा' जैसी प्रस्तुतियों ने बच्चों की ऊर्जा, उत्साह, मस्ती और आधुनिकता का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का भव्य समापन सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने गुरु एवं कोरियोग्राफर मनीष कुमार के साथ प्रस्तुत स्पेशल ग्रैंड फिनाले से हुआ, जिसे दर्शकों ने खुलकर सराहा। अंत में सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रमाणपत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। विद्यालय की डायरेक्टर रेखा बैद गुप्ता, प्रधानाचार्या श्रीमती विभा श्रीवास्तव तथा अतिथियों ने बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में डांस गुरु एवं कोरियोग्राफर मनीष कुमार ने सभी उपस्थित जनों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया।

ओम नमः शिवाय का विशाल भण्डारा शुरू, मेला क्षेत्र के आधा दर्जन प्रमुख स्थानों पर श्रद्धालु खा रहे खाना

अन्न दान से करनी है सभी की सेवा : गुरुदेव

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। माघ मेला, अर्द्धकुंभ, महाकुंभ में 49 वर्ष से सबसे विशाल अन्न क्षेत्र चलाने वाली प्रमुख संस्था ओम नमः शिवाय प्रयागराज की ओर से आज से मेला क्षेत्र के आधा दर्जन प्रमुख स्थानों पर विशाल भण्डारा दिन, रात शुरू हो गया है जहां बडी संख्या में श्रद्धालु और मेला क्षेत्र में काम करने विभागों के बडी संख्या में कर्मचारी भण्डारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे है। यह भण्डारा माघ मेले के दौरान दिन, रात चलता रहेगा जिसमें श्रद्धालु दिन, रात परिवार सहित प्रसाद लेते है।

ओम नमः शिवाय का भण्डारा मेला क्षेत्र में लाल रोड, किला चौराहा, त्रिवेणी रोड, मेला प्रशासन कार्यालय के सामने, संगम अपर मार्ग और दारागंज रामदेशिक संस्कृत विधालय के सामने चलता है जहां प्रतिदिन बडी संख्या में श्रद्धालु और मेला क्षेत्र में काम करने वाले हजारों कर्मचारी दिन, रात प्रसाद ग्रहण कर रहे है। ओम नमः शिवाय के स्वयं सेवक श्रद्धापूर्वक लोगो को भण्डारे का प्रसाद खिला रहे है।

ओम नमः शिवाय के शिविर व्यवस्थापक शिवम ने बताया कि विशाल भण्डारा आज से शुरू हो गया है। सबसे प्रमुख भण्डारा परेड की लाल रोड मे शुरू हो गया है जहां से खाना बनने के बाद मेला के क्षेत्र के कई स्थानो और संगम तक श्रद्धालुओं और कर्मचारियों में खिलाया जा रहा है जबकि अगले तीन, चार दिनों में किला चौराहा, त्रिवेणी रोड, मेला प्रशासन कार्यालय के सामने, संगम अपर मार्ग और दारागंज रामदेशिक संस्कृत विधालय के सामने दिन, रात भण्डारा शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि खाने में पूड़ी, कचौडी, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, हलवा,

रसगुल्ला, डोसा, तहरी, रायता, पापड, कढी, चावल, बूंदी, दाल सहित अन्य खाद्य सामग्रियां श्रद्धालुओं और कर्मचारियों को खाने के लिए दिया जा रहा है। ओम नमः शिवाय के पूज्य गुरुदेव ने सहयोग के लिए मेला प्रशासन के अफसरों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि अन्नदान से सबकी सेवा करता रहूंगा जिससे कि मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को खाने की कोई परेशानी ना होने पाये। उल्लेखनीय है कि ओम नमः शिवाय की ओर से प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर और अयोध्या मे लाक डाउन के दौरान और वर्तमान मे सभी जिलों के मेडिकल कालेज, चिल्ड्रन हास्पिटल और विश्व विधालयों के छात्र, छात्राओं को निःशुल्क खाना सुबह, शाम पांच वर्ष से खिलाया जा रहा है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहब्बतगंज का वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह संपन्न

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहब्बतगंज, चाका प्रयागराज का वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पार्षद बालराज पटेल एवं पार्षद संजय कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ में हुआ।

मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय के प्रयासों की सराहना की तथा उन्हें देश का आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में प्रधानाचार्य पूर्णिमा देवी ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं खेल की उपलब्धियां का उल्लेख किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। इसमें कजरी नृत्य, लोकगीत एवं स्टॉप वूमंस वायलेंस विषय पर आधारित नाटक ने सभी का मन मोह लिया। प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया एवं बोर्ड परीक्षा 2025 की मेधावी छात्राओं सलोनी, संयोगिता एवं अंशिका को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की अध्यापिका सविता गुप्ता द्वारा किया गया एवं विद्यालय के शिक्षक गण हेमलता जायसवाल, आनंद कुमार यादव , रविता गोंड, अमित सिंह , सरोज कुमारी, सविता कुमारी एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी अनुराग द्वारा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अमूल्य सहयोग दिया गया।

जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न

विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों का उज्जवल भविष्य : सचिव भगवती सिंह

शिवांश यादव प्रथम, श्लोक त्रिपाठी द्वितीय, वैष्णवी तिवारी तीसरे स्थान पर मारी बाजी

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन आज केपी इण्टर कालेज में किया गया जिसकी मुख्य थीम थी कि वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। प्रतियोगिता का शुभारम्भ मुख्य अतिथि यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने किया जबकि अध्यक्षता डीआईओएस प्रयागराज पीएन सिंह ने किया। जनपद विज्ञान प्रदर्शनी के कोऑर्डिनेटर डॉ लालजी यादव ने विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। स्वागत प्रधानाचार्य डॉ योगेंद्र सिंह एवं संचालन उमेश कुमार खरे ने किया प्रतियोगिता में 90 मॉडल से अधिक जनपद के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया।

मुख्य अतिथि यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन से विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होने कहा कि आज विज्ञान हम सबके जीवन में जन्म से मृत्यु तक समाहित है, जो काम सैकड़ो लोग महीनों में नहीं कर सकते, आज विज्ञान के कारण एक व्यक्ति कुछ मिनट में वह कार्य कर लेता है। उन्होंने कहा कि भारत के महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ घोष, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, सी बी रमन, होमी जहांगीर भाभा आप में से आगे चलकर कोई बने यह हमारी शुभकांक्षा है। विज्ञान प्रदर्शनी में शिवांश यादव नव्य करनी ऊर्जा का मॉडल प्रस्तुत कर प्रथम स्थान, दूसरे स्थान पर श्लोक त्रिपाठी सेवा का साथी मॉडल प्रस्तुत कर, तीसरे स्थान पर वैष्णवी तिवारी प्राकृतिक अकार्बनिक खेती, चौथे स्थान पर अवधेश कुमार गुप्ता वूमेन सेफ्टी पर मॉडल के साथ रहे, पांचवें स्थान पर उज्जवल यादव सेंसर टेक्नोलॉजी माडल प्रस्तुत किया।

इस दौरान10 सांत्वना पुरस्कार दिए गए जिसमें अंकुश त्रिपाठी सेंसर टेक्नोलॉजी, सम्राट विश्वकर्मा इमरजेंसी जनरेटर, आराध्या सिंह नव्य करनी ऊर्जा, महनूर फातिमा सेंसर तकनीक, अनुराधा बिंद चार्जिंग स्टेशन, जैसे मॉडल प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। सभी प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को सहभागिता प्रमाण पत्र एवं विजेता टॉप 15 विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह एवं नगद धनराशि, देकर सम्मानित किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन में संदीप कुमार, डॉ संजय श्रीवास्तव, इंदू रानी पटेल, राम सेवक कटियार, ओपी सिंह, डॉ रिकू बसु, पूर्णिमा निरखी, राजेश शुक्ला, आनंद श्रीवास्तव, फातिमा बानो, राकेश कुमार आदि का सहयोग सराहनी रहा।

कल्याण रोड पर सड़क चौड़ीकरण का विरोध तेज

विधायक रईस शेख के खिलाफ लगे नारे

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी । मास्टर प्लान और मेट्रो परियोजना के नाम पर भिवंडी पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही तोड़क कार्रवाई को लेकर स्थानीय नागरिकों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कल्याण रोड के रहिवासियों ने गुरुवार को पालिका की सड़क मार्किंग प्रक्रिया के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और स्थानीय विधायक रईस शेख के खिलाफ 'मुर्दाबाद' के नारे लगाए। जानकारी के अनुसार, पिछले महीने अंजूरफाटा से कल्याण नाका तक पालिका प्रशासन ने भारी बंदोबस्त के बीच 36 मीटर सीमा के भीतर आने वाली कई इमारतों, मकानों और दुकानों पर कार्रवाई की थी। गुरुवार को इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कल्याण नाका से राजनोली बाइपास तक सड़क किनारे मार्किंग की गई। जैसे ही यह खबर स्थानीय नागरिकों तक पहुंची, वे बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और सड़क चौड़ीकरण के इस कदम का विरोध किया।प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि जब विधायक रईस शेख ने शांतिनगर की सभा में प्रभावित लोगों को 600 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद लाने का दावा किया था, तो नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र में वे मुआवजे की मांग क्यों कर रहे थे। इससे क्षेत्र के लोगों में भ्रम और नाराजगी बढ़ गई है।व्यापारियों ने बताया कि कल्याण रोड पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर वे पहले ही तीन बार अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गंवा चुके हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार का मुआवजा या सरकारी सहायता नहीं मिली। उनका कहना है कि जो थोड़ा-बहुत हिस्सा बचा है, उसी पर वे अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं। पालिका द्वारा प्रस्तावित छह मीटर अतिरिक्त तोड़क कार्रवाई से उनकी आजीविका पर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने पालिका प्रशासन से अपील की है कि जब तक उचित मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक किसी भी तरह की नई तोड़क कार्रवाई न की जाए। विरोध प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

जानबूझकर कर किया गया विकास कार्य ठप, नागरिक परेशान !

सड़क और गटर मरम्मत कार्यों की अनदेखी का आरोप - श्याम अग्रवाल,पूर्व नगरसेवक

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी पालिका क्षेत्र में पिछले कई महीनों से विकास कार्यों की उपेक्षा को लेकर नागरिकों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। वार्ड क्रमांक 22 के नगरसेवक श्याम मनसुखराय अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में सड़क और गटरों की मरम्मत का काम जानबूझकर इंजिनियरों ने रोक दी है, जिसके चलते स्थानीय लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं।नगरसेवक अग्रवाल ने आयुक्त और संबंधित विभाग को भेजे गए पत्र में कहा है कि क्षेत्र में अनेक स्थानों पर सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। गटर और नालों की सफाई तथा मरम्मत न होने से बारिश के मौसम में पानी सड़कों पर भर जाता है और नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी संकट मंडरा रहा है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण कोई सुधार नहीं हो सका।
अग्रवाल का कहना है कि वार्ड की? समस्या को लेकर पिछले दो वर्षों से बार-बार लिखित सूचना देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कई स्थानों पर गड्ढों के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है, वहीं जाम गटरों से फैलने वाली दुर्गंध से आसपास के घरों में रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है और नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्थानीय नागरिकों की तरफ से लगातार शिकायतें की गईं, परंतु संबंधित विभाग की निरंतर लापरवाही के कारण समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। नगरसेवक ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिनों के भीतर इन मरम्मत कार्यों की शुरुआत नहीं की गई, तो नागरिकों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। अग्रवाल ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए तुरंत सड़क और गटरों की मरम्मत शुरू की जाए, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके और समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जा सके।

भिवंडी डंपिंग ग्राउंड अब एनजीटी मानकों के अनुसार होगा संचालित

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका द्वारा उद्यान के लिए आरक्षित मैदान पर बिना प्रक्रिया किए कचरा डंप किए जाने का मामला शुक्रवार को नागपुर में चल रहे राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में उठाया गया। भिवंडी पूर्व के समाजवादी पार्टी विधायक रईस शेख ने इस मुद्दे पर लक्षवेधी सूचना प्रस्तुत की, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधानसभा में विधायक रईस शेख ने बताया कि भिवंडी में प्रतिदिन लगभग 450 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिस पर किसी प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं होती। इससे स्थानीय नागरिक परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में महानगरपालिका एक भी स्थायी डंपिंग ग्राउंड विकसित नहीं कर पाई है। इस मुद्दे पर कई आंदोलनों के बावजूद मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, फिर भी नगर विकास विभाग निष्क्रिय बना हुआ है।शेख ने यह भी बताया कि मुंबई महानगर क्षेत्र में सामूहिक नागरी सुविधाएं विकसित करने के लिए एमएमआरडीए द्वारा परिपत्र जारी किया गया था, लेकिन कई महीनों से इस पर एक भी बैठक नहीं हुई है।उनके सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि ठाणे जिलाधिकारी ने डंपिंग ग्राउंड के लिए नई जगह मंजूर कर दी है। जब तक नया डंपिंग ग्राउंड तैयार नहीं होता, तब तक मौजूदा स्थल पर कचरा प्रबंधन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के मानकों के अनुसार किया जाएगा। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि 15 दिनों के भीतर विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर इस मामले का त्वरित समाधान निकाला जाएगा।स्थानीय नागरिकों को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित इस समस्या का अब ठोस समाधान मिल सकेगा।

17 दिसंबर को सपा भिवंडी पश्चिम की ओर से 'वूमेन सोशल एम्पावरमेंट समिट'

महिलाओं को सरकारी योजनाओं, अधिकारों और कौशल विकास की मिलेगी जानकारी

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। समाजवादी पार्टी भिवंडी वेस्ट इकाई की ओर से महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'वूमेन सोशल एम्पावरमेंट समिट' का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे समाजवादी कार्यालय, हुमैरा पार्क, सहिल होटल (धोबी तालाब) के पास आयोजित होगा। समिट के दौरान महिलाओं को सरकारी योजनाओं, दस्तावेज़ संबंधी जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकारों तथा कौशल विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उपयोगी मार्गदर्शन दिया जाएगा। आयोजकों के मुताबिक, कार्यक्रम का उद्देश्य वंचित और जरूरतमंद महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें विभिन्न सरकारी व सामाजिक अवसरों से जोड़ना है।समारोह में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन और पर्यवेक्षण महाराष्ट्र प्रदेश सचिव एवं भिवंडी पश्चिम के ऑब्ज़र्वर रियाज़ आज़मी के नेतृत्व में किया जाएगा।स्थानीय इकाई ने बताया कि समिट को लेकर क्षेत्र की महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में सहभागिता की उम्मीद है।

मस्जिद में गया था नमाज पढ़ने,चोरों ने जेब से उड़ा दिया मोबाइल फोन,केस दर्ज

भिवंडी।भिवंडी के आज़मी नगर स्थित दरगाह में नमाज अदा करने गए एक युवक की जेब से मोबाइल फोन की चोरी होने की घटना सामने आई है। इसे लेकर दरगाह क्षेत्र में नमाजियों में सनसनी फैल गई है। इस मामले में भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार भिवंडी के निजामपुरा इलाके में स्थित मुर्गी मोहल्ले में रहने वाला, इमरान मोहम्मद अमीन मोमिन (32) 21 नवंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे आज़मी नगर स्थित दीवानशाह दरगाह में नमाज अदा करने गए थे।नमाज खत्म होने के बाद जैसे ही वह दरगाह से बाहर निकलने लगा ,इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पेंट की जेब रखा 30,000 रुपये का मोबाइल फोन चुरा लिया और फरार हो गए अपने साथ हुए चोरी की जानकारी होने के बाद इमरान ने भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में जाकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।पुलिस केस दर्जकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।लेकिन दरगाह जैसे क्षेत्र में चोरों द्वारा हाथ की सफाई की घटना के उजागर होने से अन्य नमाजियों में सामानों की सुरक्षा को लेकर भय का माहौल व्याप्त है।

राष्ट्रपति मुर्मू का मणिपुर दौरे का दूसरा दिन, नुपी लाल स्मारक पर दी श्रद्धांजलि

इंफाल।भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से मणिपुर के दो दिवसीय दौरा पर हैं। राष्ट्रपित मुर्म अपने दूसरे दिन के दौरे में नुपी लाल स्मारक परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की। यह राष्ट्रपति मुर्मू का पहला दौरा है, जब से वे भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। उनका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सितंबर 2025 में मणिपुर दौरे के तीन महीने बाद हो रहा है।

इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा, 'भारत के राष्ट्रपति ने नुपी लाल (ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ महिलाओं का युद्ध) पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं मणिपुर की जनता की ओर से राष्ट्रपति का स्वागत करता हूं।'
राष्ट्रपति दौरे के चलते मणिपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कारण है कि कई आंतरिक सशस्त्र संगठन और प्रतिबंधित समूहों ने राष्ट्रपति दौरे के विरोध में बंद बुलाया है। इस कारण इंफाल घाटी में बाजार, स्कूल-कॉलेज बंद हैं और सड़कें सुनसान हैं। राष्ट्रपति के दौरे वाले स्थानों पर कई पोस्टर और अस्थायी प्रवेश द्वार भी लगाए गए हैं।

सिडको, पीएमसी, जन प्रतिनिधियों के विकास प्रकल्पों की निगरानी के संबंध में सरकार एक संयुक्त समिति के गठन पर उचित निर्णय लेगी।- नगरीय विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल

नागपुर। नगरीय विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने विधान परिषद को बताया कि सिडको और पीएमसी सीमा के भीतर विकास कार्यों की योजना बनाने, चल रहे विकास कार्यों की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए मनपा प्रतिनिधियों, सिडको प्रतिनिधियों और जन प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाने के लिए सरकार स्तर पर उचित निर्णय लिया जाएगा।
इस संबंध में सदस्य विक्रांत पाटिल द्वारा विधान परिषद में प्रस्तुत चर्चा में सदस्य प्रवीण दारकेकर ने लक्षवेधी के माध्यम से भाग लिया।
नवी मुंबई, पनवेल मनपा, नैना प्रकल्प क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विकास कार्य और परियोजनाएं चल रही हैं। राज्यमंत्री श्रीमती मिसाल ने यह भी कहा कि इन विकास कार्यों और परियोजनाओं की नियमित रूप से मुख्यमंत्री के वॉररूम के माध्यम से समीक्षा की जा रही है। मिसाल ने कहा कि जैसे-जैसे पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहरी इलाके में बढ़ रहा है, पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सरकार को एक रिवाइज़्ड अर्बन डेवलपमेंट प्लान दिया है, जिसमें सड़कें और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिवाइज़्ड और इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान मंज़ूरी के लिए सरकार के पास विचाराधीन है।
खारघर कोस्टल रोड, खारघर सेक्टर-16 में DAV स्कूल से शुरू होगी और CBD बेलापुर के रास्ते सीवुड्स सेक्टर-52 में 3इए स्कूल के पास पाम बीच रोड से जुड़ेगी। साथ ही, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उत्तर में सड़क पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीमा के अंदर नए पनवेल रोड के लिए उपलब्ध है और इस सड़क को एक कनेक्टिंग रोड के ज़रिए खारघर कोस्टल रोड से जोड़ने का प्रस्ताव विचाराधीन है, राज्य मंत्री श्रीमती मिसाल ने कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के काम में सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जाएगा।

17 वर्ष 8 महीने की किशोरी लापता, पुलिस ने मामला दर्ज किया

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी तालुका के एक गांव क्षेत्र से 17 वर्ष 8 महीने की एक किशोरी लापता होने की घटना सामने आई है। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निजामपुर पुलिस थाना ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी हैं। सुरक्षा कारणों से किशोरी की पहचान उजागर नहीं की गई है। किशोरी सुबह अपने सहेली के साथ पोगांच जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन निर्धारित समय तक वापस नहीं लौटी। परिवार ने आसपास के स्थानों पर खोजबीन की, पर कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने क्षेत्र में जांच शुरू कर दी। संभावित स्थानों पर पड़ताल की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस टीम विभिन्न कोणों से मामले की जांच में जुटी है। परिवार की ओर से बताया गया कि किशोरी की गुमशुदगी पूरी तरह अचानक हुई है और पहले किसी तरह की असामान्य स्थिति सामने नहीं आई थी।जिसकी आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक बडगिरे कर रहे हैं।

खाली जगह का इस्तेमाल करने वालों और बिना इजाज़त के फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने सभी डिपार्टमेंट ऑफिस एरिया में गैर-कानूनी तरीके से खाली जगह का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई शुरू की है। बेलापुर डिवीजन की तरह ही, आज वाशी डिवीजन में सेक्टर 17 और सेक्टर 2 एरिया में भी गैर-कानूनी तरीके से खाली जगह का इस्तेमाल करने वाले बिजनेसमैन के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनका सामान ज़ब्त करके कोपरखैरने में जमा कर दिया गया।
इसी तरह का ऑपरेशन सेक्टर 19 में APMC मार्केट एरिया में भी किया गया और वहां भी बिना इजाज़त के खाली जगह का इस्तेमाल करने वाले बिजनेसमैन का सामान ज़ब्त कर लिया गया। इस ऑपरेशन में 1 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही, वाशी, तुर्भे, कोपरखैरने, घनसोली डिवीजन में भी बिना इजाज़त के फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह, सभी डिवीजन में बिना इजाज़त के बैनर हटाने का कैंपेन चलाया गया।
मनपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के निर्देशानुसार सभी विभाग कार्यालय क्षेत्रों में अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे और अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड के मार्गदर्शन में अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण, सीमांत स्थान का उपयोग करने वालों और अनधिकृत फेरीवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों के चलने के लिए सड़कें और फुटपाथ खुले रहें।

मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज मिशन के ज़रिए हम गांवों की खुशहाली की दिशा ढूंढेंगे- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के टाइटल सॉन्ग की लॉन्चिंग

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पिछले कुछ दिनों में राज्य में बाढ़ की स्थिति के कारण मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान को लागू करने में रुकावट आई थी। हालांकि, अब इस अभियान को नए सिरे से शुरू किया गया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया कि इस अभियान को लागू करने से गांवों में खुशहाली आएगी।
मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान के टाइटल सॉन्ग की लॉन्चिंग विधान भवन में काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स हॉल में हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रोग्राम में शामिल सरपंच, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को टेलीविज़न सिस्टम के ज़रिए गाइड किया। इस मौके पर रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज मिनिस्टर जयकुमार गोरे मौजूद थे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, अगर हम पिछले दस सालों में राज्य में किसी भी कैंपेन की सफलता को देखें, तो यह साफ़ है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी कैंपेन पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना सफल नहीं होता। जलयुक्त शिवार अभियान इसका एक बड़ा उदाहरण है। जलयुक्त शिवार अभियान ने पानी की लिटरेसी बढ़ाई और राज्य को पानी से भरपूर बनाने में मदद की। जलयुक्त शिवार अभियान को लागू करके महाराष्ट्र देश में 'रोल मॉडल' के तौर पर सामने आया। इसके साथ ही, नरेगा के 11-पॉइंट प्रोग्राम, फार्मलैंड अभियान को सफलतापूर्वक लागू किया गया।
गांव के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान लागू किया जा रहा है। यह कैंपेन पब्लिक पार्टिसिपेशन से सफल होना चाहिए। मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान ग्राम पंचायतों को डिजिटल, आत्मनिर्भर बनाने और गांवों के एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस कैंपेन में सहयोग करने वाले आर्टिस्ट ग्राम सभाओं में मौजूद रहेंगे। कैंपेन के लागू होने से गांवों में खुशहाली के लिए कॉम्पिटिशन होगा। इसलिए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने सभी ग्राम पंचायतों से कैंपेन में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने और इसे सफल बनाने की अपील भी की।
ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे ने कैंपेन का बैकग्राउंड समझाया। ग्रामीण विकास विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एकनाथ दावले ने आए हुए लोगों को धन्यवाद दिया।
एक्टर भरत गणेशपुरे, संदीप पाठक, पृथ्वी प्रताप, एक्ट्रेस शिवाली परब और डिपार्टमेंट के अधिकारी प्रोग्राम में मौजूद थे।
शॉर्ट में, मुख्यमंत्री का खुशहाली पंचायत राज अभियान..
ग्रामीण इलाकों में लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करने वाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लेवल पर एक कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ताकि केंद्र और राज्य सरकारों की सभी स्कीमों को और अच्छे से लागू किया जा सके। इस कॉम्पिटिशन में सबसे अच्छा काम करने वाली पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए, साल 2025-26 से तालुका, ज़िला, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और राज्य के चार लेवल पर एक कॉम्पिटिटिव तरीके से 'मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान' शुरू किया जाना चाहिए। इसे लागू किया जा रहा है।
इस अभियान के मुख्य हिस्से हैं ऐसी ग्राम पंचायतें बनाना जो मज़बूत, अच्छी तरह से चलने वाली, पानी से भरपूर, साफ़ और हरी-भरी हों, MGNREGA और दूसरी स्कीमों के साथ जुड़ी हों, रोज़ी-रोटी का विकास और सामाजिक न्याय हो, लोगों की भागीदारी और श्रमदान से लोगों का आंदोलन हो। इस अभियान के तहत अलग-अलग लेवल पर अवॉर्ड दिए जाएंगे।

परतुर रीजनल वॉटर सप्लाई स्कीम में तेज़ी आई, दो दिन में वॉटर सप्लाई ठीक हो गई- वॉटर सप्लाई और सैनिटेशन मिनिस्टर गुलाबराव पाटिल

नागपुर। वॉटर सप्लाई मिनिस्टर गुलाबराव पाटिल ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बताया कि जालना ज़िले के परतुर असेंबली इलाके में दो ज़रूरी रीजनल वॉटर सप्लाई स्कीम, 173 गाँव और 95 गाँव के काम को नई रफ़्तार देकर पूरा करने के लिए तुरंत एक्शन लिया जा रहा है।
वे मेंबर बबनराव यादव (लोनीकर) के एक खास सुझाव का जवाब देते हुए बोल रहे थे।
वॉटर सप्लाई मिनिस्टर पाटिल ने कहा कि 173 गाँव की स्कीम पर अब तक 226 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। 146 गाँवों में स्कीम का काम पूरा हो चुका है। बाकी गाँवों में हाईवे के काम की वजह से आई कुछ टेक्निकल दिक्कतों और रुकावटों को तेज़ी से ठीक किया जा रहा है। जिन गाँवों में टैपिंग पॉइंट हैं, वहाँ जल्द ही वॉटर सप्लाई शुरू हो जाएगी। 95 गाँव की रीजनल स्कीम 87 गाँवों में कामयाबी से शुरू हो चुकी है और बाकी जगहों पर बिजली बिल से जुड़ी दिक्कतों को ठीक करने के लिए डिपार्टमेंट ने तुरंत कदम उठाए हैं। मंत्री पाटिल ने कहा कि वे दो दिनों के अंदर सभी बंद गांवों में पानी की सप्लाई शुरू करने के लिए फॉलो-अप कर रहे हैं।
यह बताते हुए कि काम में गड़बड़ियों की जांच चल रही है, मंत्री पाटिल ने कहा कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। संबंधित कॉन्ट्रैक्टर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, यह पक्का करने के लिए सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। अगर ज़रूरी हुआ तो दोषी कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। केंद्र से फंड मिलने के बाद, राज्य सरकार ने तुरंत 2100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराकर पानी सप्लाई प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाई है। लोगों को पानी देना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री पाटिल ने यह भी कहा कि बाकी सभी रुकावटें दूर की जाएंगी और स्कीम को पूरी क्षमता से शुरू किया जाएगा।

बहरीन के तेज गेंदबाज अली दाऊद का टी20आई में ऐतिहासिक प्रदर्शन

रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। बहरीन के तेज गेंदबाज अली दाऊद ने भूटान के खिलाफ पुरुषों के टी20आई इतिहास में दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7-19 विकेट लेकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। 33 साल के इस तेज गेंदबाज ने मलेशिया के स्याजरुल इदरस के बाद टी20आई में 7 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं।

उनकी कोशिशों ने गेलेफू में भूटान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और पांच मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में बहरीन को 35 रन से जीत दिलाई। तीसरे ओवर में आए दाऊद ने 2 विकेट लिए जिससे मेजबान टीम 11/3 पर लड़खड़ा रही थी फिर देर से लौटे और निचले क्रम को तहस-नहस कर दिया। पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए दाऊद ने 16वें ओवर में तीन विकेट और अगले ओवर में दो और विकेट लेकर 7-19 का स्कोर बनाया। चौथे विकेट के लिए 67 रन की पार्टनरशिप के बावजूद भूटान 125 रन पर आउट हो गया, जिससे बहरीन जिसने 160/4 बनाए थे, को पांच मैचों की सीरीज़ में 2-1 की बढ़त मिल गई।

दाऊद अब तेज गेंदबाज इदरस से पीछे हैं, जिन्होंने 2023 में बायूमास ओवल में आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप एशिया बी क्वालिफायर मैच के दौरान चीन के खिलाफ शानदार 7-8 विकेट लिए थे। इत्तेफाक से उनके सभी 7 विकेट बोल्ड आउट हुए थे। सिंगापुर के हर्ष भारद्वाज (2024 में मंगोलिया के खिलाफ 6-3), नाइजीरिया के पीटर अहो (2021 में सिएरा लियोन के खिलाफ 6-5) और भारत के दीपक चाहर (2019 में बांग्लादेश के खिलाफ 6-7) मेन्स टी20आई फॉर्मेट में टॉप 5 परफॉर्मेंस में शामिल हैं। आईसीसी के फुल मेंबर्स की बात करें तो तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर चाहर के नाम पुरुषों के टी20आई में बेस्ट बॉलिंग फिगर का रिकॉर्ड है, जो नागपुर के वीसीए स्टेडियम में आया था। इस स्पेल के साथ दाऊद के 64 टी20आई में 14.10 के एवरेज से 96 विकेट हो गए हैं। उनका इकॉनमी रेट सिर्फ 5.96 है। भूटान के खिलाफ टी20आई में उनका पहला पांच विकेट था, इसके अलावा दाऊद ने तीन बार चार विकेट भी लिए हैं।

मशहूर तेज गेंदबाज ने शुभमन गिल का किया बचाव, दो टी20आई मैच के बाद आंकने लगे तो समस्या है

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। गुजरात टाइटन्स के मुख्य कोच आशीष नेहरा कप्तान शुभमन गिल की फॉर्म पर जल्दबाजी में की जा रही आलोचनाओं से नाखुश हैं और उन्होंने कहा कि इतने उतार-चढ़ाव वाले टी20 प्रारूप में दो मैच के आधार पर किसी खिलाड़ी को खारिज कर देना जल्दी निष्कर्ष निकालने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का संकेत है।

एशिया कप के दौरान उप-कप्तान के रूप में टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में लौटे गिल ने पिछले 10 मैच में कुल 181 रन बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 140 से कम रहा है। पिछले दो सत्र में गुजरात टाइटन्स के कोच के तौर पर गिल को करीब से देखने वाले नेहरा से पूछा गया कि क्या वह चिंतित हैं जबकि आईपीएल शुरू होने में अभी तीन महीने ही बचे हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर पूर्व तेज गेंदबाज नेहरा ने कहा, 'तीन महीने तो छोड़ दो, अगर आईपीएल तीन हफ्ते बाद भी होता तब भी मैं चिंतित नहीं होता क्योंकि आप टी20 जैसे प्रारूप की बात कर रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ दो मैच ही खेले गए हैं।'

नेहरा का मानना है कि भारत में आलोचना की मूल समस्या सिर्फ संख्याओं को देखकर निष्कर्ष पर पहुंच जाना है। उन्होंने कहा, 'यही हमारी समस्या है। इस प्रारूप में (भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या आईपीएल) अगर शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को दो-तीन मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर आंका जाए तो मुश्किल होगी।' अपनी खास व्यंग्यात्मक शैली में नेहरा ने कहा कि अगर बदलाव चाहिए तो विकल्पों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, "आपके पास बहुत विकल्प हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को हटा सकते हैं तथा साई सुदर्शन और रुतुराज गायकवाड़ को पारी का आगाज करा सकते हैं।'

नेहरा ने कहा, 'अगर आप इन्हें (साई और रुतुराज) भी हटाना चाहें तो वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन से पारी का आगाज करा सकते हैं। इसलिए विकल्प बहुत हैं। अगर आप एक-दो मैच हारते हैं या किसी बल्लेबाज या गेंदबाज के आंकड़े अच्छे नहीं हैं और आप उन्हें बदलने की बात करते हैं तो फिर मुश्किल होगी। पिछले सत्र में एक तय संयोजन की वजह से सुंदर ने टाइटन्स के लिए केवल छह मैच खेले थे लेकिन नेहरा ने संकेत दिए कि अगर वह फिट रहे तो इस बार उनका उपयोग पहले से कहीं ज्यादा होगा। भारतीय टीम में सुंदर की भूमिका से संदेह बन गया है कि वह मुख्यतः बल्लेबाजी ऑलराउंडर है या एक विशेषज्ञ स्पिनर जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेता है। लेकिन नेहरा के मुताबिक सुंदर एक उच्च स्तरीय बल्लेबाज हैं और अगर पिच से मदद मिले तो वह अपनी ऑफ-स्पिन के साथ एक संपूर्ण पैकेज बन जाते हैं।

उन्होंने कहा, 'सुंदर के पास जो कौशल है, मेरे लिए वह पहले एक बल्लेबाज हैं, जो पहले से छठे या सातवें स्थान तक कहीं भी खेल सकते हैं। उनके पास इतनी क्षमता है। और जहां तक आपके सवाल की बात है (बल्लेबाज या गेंदबाज) तो यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

एसएमएटी : नीतीश रेड्डी की हैट्रिक बेकार गई, 4 विकेट से हारा आंध्र प्रदेश

पुणे **(एजेंसी)**। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की हैट्रिक ने आंध्र को उम्मीद की एक किरण दी लेकिन मध्य प्रदेश ने 14/3 से उबरते हुए 113 रन का पीछा किया और डीवाई पाटिल अकादमी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सुपर लीग स्टेज के अपने पहले मैच में चार विकेट से जीत हासिल की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद घरेलु टूर्नामेंट में खेल रहे रेड्डी आंध्र टीम में शामिल हुए थे। उन्होंने तीसरे ओवर में हर्ष गवली, हरप्रीत भाटिया और रजत पाटीदार को आउट किया।

वेंकटेश अय्यर के आउट होने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश का स्कोर 37/4 हो गया और जीत की उम्मीद जगी। लेकिन ऋषभ चौहान और राहुल बाथम के बीच पांचवें विकेट के लिए 73 रन की शानदार साझेदारी ने टीम को संभाल लिया। चौहान ने 43 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 47 रन बनाए जबकि बाथम 32 गेंदों पर 35 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे मध्य प्रदेश ने 15 गेंद बाकी रहते जीत हासिल की और चार जरूरी पॉइंट हासिल किए।

इससे पहले रेड्डी ने विकेटकीपर-बल्लेबाज केएस भरत के साथ तीसरे विकेट के लिए 50 रन जोड़े थे, जब आंध्र का स्कोर 7/2 था। भरत ने अय्यर की गेंद पर आउट होने से पहले सबसे ज्यादा 39 रन बनाए जिससे आंध्र की टीम 55 रन पर 8 विकेट खोकर 19.1 ओवर में 112 रन पर ढेर हो गई। मध्य प्रदेश के लिए शिवम शुक्ला ने 4-23 और त्रिपुरेश सिंह ने 3-31 विकेट लिए। बाथम ने 2 विकेट लिए जिससे आंध्र के चार बल्लेबाज बिना रन बनाए आउट हो गए। आंध्र का अगला मैच पंजाब के खिलाफ होगा जबकि मध्य प्रदेश का मुकाबला उसी दिन 14 दिसंबर को झारखंड से होगा।

महिला पहलवान विनेश फोगट ने संन्यास से की वापसी

तीन बार की ओलंपियन ने किया भावुक पोस्ट

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। तीन बार की ओलंपियन महिला पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कुश्ती से संन्यास लेने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। फोगाट ने भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने संन्यास से वापसी की घोषणा करते हुए कहा कि अब उनका लक्ष्य लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करना है।

पिछले साल विनेश फोगाट ने पेरिस 2024 ओलंपिक के तुरंत बाद संन्यास ले लिया था। ठीक एक दिन बाद जब उन्हें स्वर्ण पदक मुकाबले से ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित किया गया था। विनेश ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'लोग मुझसे पूछते रहे कि क्या पेरिस मेरे करियर का अंत है। लंबे समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मैट से, दबाव से, उम्मीदों से, यहां तक कि अपनी महत्वाकांक्षाओं से भी दूर हटने की जरूरत थी। इतने सालों में पहली बार मैंने खुद को चैन की सांस लेने दी।'

उन्होंने कहा, 'मैंने अपने सफर के महत्व को समझने के लिए समय लिया, ऊंचाइयों, दिल टूटने के पलों, बलिदानों और मेरे उन रूपों को समझा जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। और इसी आत्मचिंतन में मुझे सच्चाई मिली, कि मुझे अब भी इस खेल से प्यार है। मैं अब भी प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूं।'

रुपया फिर टूटा, अब तक के सबसे निचले स्तर पर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अमेरिका मुद्रा के मुकाबले रुपया शुक्रवार को नौ पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.41 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि कीमती धातुओं की वैश्विक कीमतों में उछाल के बीच आयातकों द्वारा डॉलर की आक्रामक खरीद से भी रुपए पर दबाव पड़ा।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.43 पर खुला। फिर लुढ़कता हुआ रिकॉर्ड निचले स्तर 90.56 प्रति डॉलर पर आ गया। अंत में यह 90.41 पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से नौ पैसे की गिरावट है। रुपया बृहस्पतिवार को 38 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.32 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

मीराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, "भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता के बीच रुपए में गिरावट का अनुमान है। हालांकि, वैश्विक बाजार में सकारात्मक रुझान और कच्चे तेल की गिरती कीमतें रुपए को सहारा दे सकती हैं। डॉलर के कमजोर होने और केंद्रीय बैंक के किसी भी हस्तक्षेप से भी रुपये को निचले स्तर पर समर्थन मिल सकता है।"

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.41 पर रहा। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 449.53 अंक की बढ़त के साथ 85, 267.66 अंक पर जबकि निफ्टी 148.40 अंक चढ़कर 26, 046.95 अंक पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 61.27 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 2, 020.94 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।

मध्य रेल
भुसावल मंडल
ई-निविदा सूचना

निविदा सं. :- BSL-L-W-T-63-2025 :- कार्य का विवरण : । निम्नलिखित के संबंध में विद्युतीकरण कार्य भाग ए - खेरवाडी स्टेशन पर 2027 कुंभ मेला यातायात को संभालने के लिए अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्मों के प्रावधान के लिए प्रस्तावित यार्ड रीमॉडलिंग।; भाग बी - कस्बे सुकेने स्टेशन पर 2027 में कुंभ मेला यातायात को संभालने के लिए अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्मों के प्रावधान के लिए प्रस्तावित यार्ड रीमॉडलिंग।; भाग सी - देवलाली स्टेशन पर कुंभ मेला 2027 के दौरान यात्री ट्रेनों को संभालने के लिए अतिरिक्त प्लेटफार्मों के प्रावधान के लिए प्रस्तावित यार्ड रीमॉडलिंग।; भाग डी - नासिक स्टेशन पर डाउन ट्रेन अप पीएफ-4 के स्वागत की सुविधा के लिए मुंबई छोर पर आपातकालीन क्रॉस ओवर के प्रावधान के लिए प्रस्तावित यार्ड रीमॉडलिंग।; भाग ई - ओढा स्टेशन पर 2027 में कुंभ मेला यातायात को संभालने के लिए अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्म और स्टेबलिंग लाइनों के प्रावधान के लिए प्रस्तावित यार्ड रीमॉडलिंग।; भाग एफ - ओढा स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन के लिए लंबी दूरी की विफलताओं के प्रावधान के लिए यार्ड रीमॉडलिंग।; **2) अनुमानित लागत:** रु. 9,28,70,367; **3) ऑनलाईन बिड सबमिशन का अंतिम दिनांक और समय :** 31/12/2025 को 15:00 बजे, **4) वेबसाईट विवरण: - https://www.ireps.gov.in**

Apex-18 **व.मं.बि.इं. (सा.) भुसावल**

अनाधिकृत रूप से रेल लाइन को पार करना दंडनीय अपराध है

विदेशी मुद्रा भंडार एक अरब डॉलर बढ़कर 687.26 अरब डॉलर पर

मुंबई **(एजेंसी)**। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पांच दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 1.03 अरब डॉलर बढ़कर 687.26 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.88 अरब डॉलर घटकर 686.23 अरब डॉलर रह गया था। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, पांच दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.51 अरब डॉलर घटकर 556.88 अरब डॉलर रह गईं। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड व येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल होता है। रिजर्व बैंक ने बताया कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.19 अरब डॉलर बढ़कर 106.98 अरब डॉलर हो गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) भी 9.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.72 अरब डॉलर हो गया। आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत का आरक्षित भंडार 9.7 करोड़ डॉलर घटकर 4.67 अरब डॉलर रहा।

रूस से तेल खरीद में तेज़ी, नवंबर में भारत बना दूसरा सबसे बड़ा आयातक

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत का रूस से कच्चा तेल आयात नवंबर में चार प्रतिशत बढ़कर पांच महीनों में सबसे अधिक 2.6 अरब यूरो तक पहुंच गया। इस तेल से परिष्कृत ईंधन की बड़ी मात्रा ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की गई। यूरोप के एक शोध संस्थान ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर' (सीआरईए) ने एक रिपोर्ट में कहा कि रूसी कच्चे तेल के मामले में भारत नवंबर में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा। इसके पहले अक्टूबर में भारत ने रूस से 2.5 अरब यूरो का कच्चा तेल खरीदा था।

नवंबर में रूस के कुल कच्चे तेल निर्यात का 47 प्रतिशत चीन, 38 प्रतिशत भारत, छह प्रतिशत तुर्किये और छह प्रतिशत यूरोपीय संघ के हिस्से गया। सीआरईए ने कहा कि भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात अक्टूबर की तुलना में चार प्रतिशत बढ़ गया जबकि कुल आयात मात्रा लगभग स्थिर रही। यह पिछले पांच महीनों में सर्वाधिक खरीद रही। संस्था का अनुमान है कि दिसंबर में भी यह खरीद बढ़ सकती है, क्योंकि रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने से पहले कुछ तेलवाहक जहाज रवाना हुए थे। अमेरिका ने 22 अक्टूबर को रूस की बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट एवं ल्यूकऑयल पर प्रतिबंध लगा दिए थे।

यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की धन आपूर्ति सीमित करने के इरादे से यह पाबंदी लगाई गई थी। इन प्रतिबंधों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने रूसी तेल का आयात अस्थायी रूप से रोक दिया है। हालांकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अब भी गैर-प्रतिबंधित रूसी आपूर्तिकर्ताओं से खरीद जारी रखे हुए हैं। सीआरईए ने कहा, 'नवंबर में जहां निजी तेल कंपनियों के आयात में हल्की गिरावट आई, वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी कच्चे तेल की खरीद 22 प्रतिशत बढ़ा दी।'

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भारत 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा ग्राहक बन गया। कभी एक प्रतिशत से भी कम रहा रूसी तेल आयात का हिस्सा बढ़कर भारत के कुल तेल आयात का लगभग 40 प्रतिशत हो गया। आंशिक गिरावट आने के बावजूद नवंबर महीने में रूस ने भारत की कुल कच्चे तेल आपूर्ति में 35 प्रतिशत का योगदान दिया। इस कच्चे तेल को रिफाइन कर बनाए गए पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन को घरेलू उपयोग के साथ निर्यात भी किया जाता है। सीआरईए ने कहा कि नवंबर में भारत और तुर्किये की छह रिफाइनरियों ने 80.7 करोड़ यूरो मूल्य के रिफाइंड ईंधन निर्यात किए।

मध्य रेल
ई-निविदा सूचना

खुली निविदा संख्या : १] PR-EN - 25-26-721A दि. 01/12/2025. कार्य का विवरणं: परेल कार्यशाला में ०२ निरीक्षण / धुलाई गड्ढों की ट्रैक लाइनों सहित व्यवस्था। **अनुमानित लागत:** रु. 44,42,315.10, **निविदा प्रपत्र का शुल्क:** कुछ नहीं, **ईएमडी:** रु.88,900/-. **समापन अवधि :** छह माह, वे प्रतिष्ठान जो उनकी व्यक्तिगत क्षमता मे न्यूनतम योग्यता मापदंड की पूर्तता करते हो उनसे ही यह ई-निविदा आमंत्रित की गयी है दोनों ई-निविदा की जमा करने की तिथी एवं अवधि दि. 22.12.2025 को 17.00 बजे तक है दोनों ई-निविदा की विस्तृत जानकारी रेल की आधिकारीक वेबसाइट : **https://www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है:

APEX-712 **मुख्य कारखाना प्रबंधक परेल**

अपने जानवरों को रेल लाइन से दूर रखे

गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स संग मनाया बर्थडे! पार्टी में न जाने पर तान्या मित्तल ने तोड़ी चुप्पी

बिग बॉस 19 का सीजन तो खत्म हो गया लेकिन फिर भी कंटेस्टेंट्स काफी सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। कुछ के बीच दोस्तो हो गई और कुछ अभी भी दुश्मनी मना रहे हैं। हालिए में 11 दिसंबर को बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना ने अपना बर्थडे पार्टी का आयोजन किया, जिसमें लगभग सभी कंटेस्टेंट नजर आएं। हालांकि, बिग बॉस की थर्ड रनर-अप रहीं तान्या मित्तल ने शो से निकलते ही सभी घरवालों से दूरी बना ली है। गौरवा की शानदार बर्थडे पार्टी पर तमाम बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स नजर आएं, लेकिन तान्या मित्तल इस पार्टी में नजर नहीं आई। अब तान्या मित्तल ने बताया कि मुंबई में रहकर के बावजूद भी वह क्यों गौरव की पार्टी में शामिल नहीं हुईं।

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 के घर में तान्या मित्तल के खिलाफ सभी कंटेस्टेंट्स जा चुके हैं। किसी ने उनके परिवार पर कमेंट किया तो किसी ने उन्हें फेक बताया। इसलिए तान्या मित्तल उन लोगों से नहीं मिलना चाहती, जिन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में तान्या ने गौरव की पार्टी में न जाने की वजह बताई है।

मैं नहीं जाऊंगी। मैंने क्लियर कर दिया है कि जिन भी लोगों ने मेरी बेइज्जती की है और जीके सर ने तो ये भी बोला है कि मैं अपना परिवार छुपा रही हूं ताकि मेरा सच सामने न आ जाए। तो जब मेरे परिवार पर ही भरोसा नहीं तो मैं वहां जाकर उन्हें किस बात का यकीन दिलाऊं। इतना ही नहीं, बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में ही मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल से गौरव की पार्टी में आने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मृदुल ने इंटरव्यू में कहा कि तान्या उन्हें एटीट्यूड दिखा रही थीं।

आपको बताते चले कि तान्या मित्तल के अलावा गौरव खन्ना की बर्थडे पार्टी में बिग बॉस 19 की फर्स्ट रनर-अप रहीं फरहाना भट्ट भी नहीं गई थीं। उनके अलावा मालती चाहर और बसीर अली भी पार्टी से गायब दिखे।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

वृक्ष प्राधिकरण
-सार्वजनिक सूचना-

महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण एवं परिरक्षण अधिनियम 1975 (जनवरी 2018 तक संशोधित) की धारा 8 (3) (सी) के तहत प्रावधान के अनुसार, जोन-VI में 'एन' वार्ड से 01 प्रस्ताव और 'टी' वार्ड से 01 प्रस्ताव यानी पेड़ों को हटाने के कुल- 02 प्रस्तावों को नगर आयुक्त, अध्यक्ष, वृक्ष प्राधिकरण बीएमसी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा (8) की उपधारा (6) के तहत अनुमोदित किया जाता है।
उपर्युक्त प्रस्तावों में काटने/प्रतिरोपण के लिए पेड़ों की जानकारी बीएमसी वेबसाइट https://portal.mcgm.gov.in/About us Ward / Department Manuals / Gardens & Tree Authority. 108 (N) & 109 (T) पर उपलब्ध है।

उद्यान एवं वृक्ष अधीक्षक अधिकारी
उद्यान अधीक्षक तथा वृक्ष अधिकारी का कार्यालय,
द्वितीय तल, हंबोल्ट पेंगुइन भवन,
वी. जे. बी. वनस्पति उद्यान एवं प्राणीसंग्रहालय,
संत सावतामाली मार्ग,
भायखला (पूर्व), मुंबई - 400027
फ़ोन नंबरः 23742162
ई-मेल : sg.gardens@mcgm.gov.in

पीआरओ/2636/विज्ञा./2025-26 **उद्यान अधीक्षक एवं वृक्ष अधिकारी**

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने वडोदरा-गोधरा-आणंद रेल खंड का किया संरक्षा निरीक्षण

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने 12 दिसम्बर 2025 को वडोदरा मंडल के वडोदरा - गोधरा - आणंद रेल खंड एवं प्रतापनगर कारखाने का वार्षिक संरक्षा निरीक्षण किया। अपने संरक्षा निरीक्षण में उन्होंने वडोदरा - गोधरा - आणंद रेलखंड में संरक्षा एवं सुरक्षा मानकों, ढांचागत विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं, कर्मचारियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं तथा अन्य प्रगति कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया। आणंद स्टेशन पर महाप्रबंधक ने आणंद के माननीय विधायक योगेश पटेल ज़ी एवं डाकोर स्टेशन पर थासरा के माननीय विधायक योगेंद्र सिंह परमार ज़ी से मुलाकात की एवं उन्हें मंडल के विकास कार्यों एवं यात्री सुविधाओं की जानकारी दी। महाप्रबंधक के साथ विभिन्न विभागों के प्रमुख विभागाध्यक्ष, वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके , अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

अपने वार्षिक संरक्षा निरीक्षण के दौरान गुप्ता ने रोड अंडर ब्रिज, महत्त्वपूर्ण बड़े एवं छोटे पुलों, सेक्शनल स्पीड ट्रायल, पॉइंट एवं क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग सहित विभिन्न संरक्षा तत्वों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने वडोदरा, गोधरा, डेरोल एवं डाकोर स्टेशनों पर यात्री प्रतीक्षालय, टिकट बुकिंग सुविधा, शुद्ध पेय जल, पैदल ऊपरी पुल आदि उपलब्ध यात्री सुविधाओं का भी विस्तृत जायजा लिया।

छायापुरी यार्ड में महाप्रबंधक गुप्ता ने पॉइंट एवं क्रासिंग तथा इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन, सिग्नलिंग एवं टेलीकम्यूनिकेशन गैंग का निरीक्षण किया और रेल कर्मियों से संरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने छायापुरी - डेरोल खंड के बीच स्पीड ट्रायल का निरीक्षण भी किया।

गोधरा में गुप्ता ने रेलवे स्टेशन के अलावा रेलवे कॉलोनी, गार्ड एवं ड्राइवरों के रनिंग रूम, RPF बैरक का निरीक्षण किया। उन्होंने गोधरा में रेलवे कम्युनिटी हाल का उद्घाटन भी किया।

गोधरा - आणंद खंड पर उन्होंने महत्त्वपूर्ण बड़े एवं छोटे पुलों तथा कर्व के साथ - साथ डेरोल - खरसलिया एवं उमरेठ - आनंद खंड पर लेवल क्रासिंग गेट का निरीक्षण किया।

गुप्ता ने अपने दौरे के दौरान डेरोल एवं गोधरा में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया एवं मंडल के उपलब्धिओं एवं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वडोदरा मंडल द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। डेरोल, गोधरा और डाकोर में गुप्ता ने रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया और रेलकर्मियों को गोधरा एवं डाकोर रेलवे कॉलोनी में उनके नए आवास की चाबी का वितरण भी किया।

महाप्रबंधक ने यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए संबंधित अधिकारियों को ट्रैक, समपार फाटकों तथा अन्य संरक्षा मानकों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए, ताकि ट्रेन सेवाएँ अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और समयानुसार संचालित की जा सकें।

गायक जुबीन गर्ग मौत मामला : एसआईटी ने दायर की चार्जशीट, चार आरोपियों पर हत्या का आरोप

नई दिल्ली। असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने कामरूप मेट्रो के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है। जुबीन की मौत 19 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता बिजन महाजन ने बताया कि 3,500 पन्नों की चार्जशीट में बड़ी कार्रवाई करते हुए सात गिरफ्तार व्यक्तियों में से चार पर धारा 103 (भारतीय न्याय संहिता - बीएनएस) के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है।

हत्या के आरोपितों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानू महंत, गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, ड्रमर शेखरज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत शामिल हैं। अगर आरोप सिद्ध होता है तो बीएनएस की धाराओं के तहत मौत की सजा या उम्रकैद तक हो सकती है। वहीं जुबीन के चचेरे भाई और निलंबित एपीएस अधिकारी संदीपान गर्ग पर धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत आरोप तय किया गया है। इस धारा में अपराध की प्रकृति के अनुसार उम्रकैद से लेकर 5-10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसी के साथ, गायक को सुरक्षा प्रदान करने वाले दोनों पीएसओ परेश बैश्य और नंदेश्वर बोरा पर आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए हैं, जिससे इस मामले की जटिलता और बढ़ गई है। इस बीच, सिंगापुर पुलिस बल भी अपनी स्वतंत्र जांच कर रहा है। उनका कहना है कि अब तक की प्रारंभिक जांच में किसी फाउल प्ले के संकेत नहीं मिले, और पूरी जांच में तीन महीने का समय लग सकता है।

असम विधानसभा के हालिया सत्र में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया था कि जुबीन गर्ग की मौत 'साफ-साफ हत्या' है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब अदालत में आगे की प्रक्रिया यह तय करेगी कि इस उच्च-प्रोफाइल और भावनात्मक रूप से संवेदनशील मामले की दिशा आगे क्या रूप लेगी। उल्लेखनीय है कि जुबीन गर्ग 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

नीयत धुंधली और स्वार्थ की राजनीति...उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा

नई दिल्ली। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) में नए सिरे से दरार पैदा हो गई है, क्योंकि पार्टी के विधायक शीर्ष नेतृत्व से असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। पार्टी विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सच्ची मंशा और मजबूत नीतियों से हासिल होती है। सोशल मीडिया पर रामेश्वर महतो ने कहा कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सच्ची मंशाओं और मजबूत नीतियों से भी मिलती है। जब नेतृत्व की मंशाएं अस्पष्ट हो जाती हैं और नीतियां जनहित की बजाय स्वार्थ की ओर झुकने लगती हैं, तो जनता को लंबे समय तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है; वह हर कदम, हर निर्णय और हर मंशा का बारीकी से विश्लेषण करता है।

ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि रामेश्वर महतो मंत्री पद न मिलने से बेहद नाराज हैं। दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद दिलाने में कामयाब रहे। यह लंबे समय से पार्टी के भीतर विवाद का मुद्दा रहा है, और विधायक की नियुक्ति से इन अटकलों को और बल मिलता दिख रहा है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब किसी पार्टी विधायक ने पार्टी नेतृत्व के प्रति असंतोष व्यक्त किया हो। दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के मंत्री बनने के बाद से लगातार पार्टी के भीतर आपत्तियां उठाते रहे हैं। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान भी विधायकों के बीच फूट साफ तौर पर दिखाई दी थी।

हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने माधव आनंद को विधायक दल का नेता और पत्नी स्नेहलता को मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में छह सीटों पर चुनाव लड़ा और चार पर जीत हासिल की। आरएलएम के भीतर भाई-भतीजावाद को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब रामेश्वर महतो की पोस्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विधायक महतो की पोस्ट ने पार्टी को एक नए राजनीतिक संकट में डाल दिया है। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक करियर हमेशा उतार-चढ़ाव से भरा रहा है, और अब उनके अपने ही विधायक की नाराजगी ने आरएलएम के भीतर विवाद का एक नया कारण पैदा कर दिया है।

कंबोडिया और थाईलैंड जंग में हिंदू मंदिर को नुकसान, एक्शन में आया भारत, एमईए ने दी नसीहत

नई दिल्ली।विदेश मंत्रालय (एमईए) ने हाल ही में थाईलैंड-कंबोडिया संघर्ष के दौरान प्रेह विहार हिंदू मंदिर को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, 1,100 साल पुराने इस मंदिर को दोनों पड़ोसी देशों के बीच फिर से शुरू हुए सीमा संघर्ष के दौरान नुकसान पहुंचा है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोनों देशों के बीच हाल ही में बढ़े तनाव पर चिंता व्यक्त की। बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि संरक्षण सुविधाओं को कोई भी नुकसान दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है।

रणधीर जायसवाल को मंदिर की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भरोसा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, प्रेह विहार मंदिर, मानवता की साझा सांस्कृतिक विरासत है। भारत इसके संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस स्थल और संबंधित संरक्षण सुविधाओं की पूर्ण सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हम दोनों पक्षों से एक बार फिर संयम बरतने और शत्रुता समाप्त करने तथा तनाव को और बढ़ने से रोकने के उपाय करने की अपील करते हैं। हम उनसे संवाद और शांति के मार्ग पर लौटने का आग्रह करते हैं।

कंबोडिया और थाईलैंड के बीच झड़पें फिर से शुरू हो गईं, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता से जुलाई में पांच दिनों तक चले क्षेत्रीय विवादों पर हुए संघर्ष के बाद संपन्न हुआ युद्धविराम समाप्त हो गया। थाई सेना ने गुरुवार को बताया कि कंबोडिया के साथ थाईलैंड की सीमा पर भीषण संघर्ष के दौरान तीन थाई नागरिक मारे गए। यह घटना पिछले सप्ताह हुई एक झड़प के बाद भड़की व्यापक लड़ाई के बाद हुई, जिसमें दो थाई सैनिक घायल हो गए थे। इस बीच, नवीनतम संघर्ष में लगभग 24 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि सीमा के दोनों ओर लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। इस बीच, प्राचीन प्रेह विहार मंदिर दोनों पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने बुधवार को मंदिर के आसपास हो रही लड़ाई पर अपनी 'गहरी चिंता' व्यक्त की, जिसे उसने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है।

बीच समंदर हथियारबंद अमेरिकी कमांडोज ने वेनेजुएला जहाज पर किया हमला

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन और पीएम मोदी की यात्रा से बौखलाए हुए अमेरिका ने वही किया जिसका डर था। लेकिन इसके बाद रूस ने भी वही किया जिसकी उम्मीद थी। अमेरिका ने भारत और रूस के एक मित्र देश पर हमले की शुरुआत कर दी है। यह देश वेनेजुएला है जो तेल के अपार भंडार पर बैठा है। वही तेल जिसके लिए अमेरिका ने कई देशों को बर्बाद कर दिया। अमेरिकी सेना के कमांडोज़ ने वेनेजुएला पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। कारण तस्करी बताया गया है लेकिन असली खेल तेल का ही है। दिलचस्प बात यह है कि वेनेजुएला के साथ भारत और रूस दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। हाल ही में भारत ने वेनेजुएला के साथ एक बहुत बड़ी डील की थी और रूस भी लगातार वेनेजुएला को संरक्षण दे रहा है। तभी तो वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन के बाद पुतिन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है।

दरअसल बीच समंदर अमेरिका के हथियार बंद कमांडोज वेनेजुएला के एक बहुत बड़े क्रूड ऑयल टैंकर पर उतरे और पल भर में उस पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के दो सैन्य हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर तेजी से उड़ते हुए आए और टैंकर को घेर लिया। कई अमेरिकी कमांडोज़ रस्सियों के सहारे टैंकर के डेक पर उतर गए और कुछ ही मिनटों में टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। वेनेजुएला ने अमेरिका के एक्शन को समुद्री डकैती और खुलेआम चोरी करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। ट्रंप रूस, यूक्रेन, भारत, बांग्लादेश, यूरोप, खाड़ी देशों सभी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। किसी को टेरिफ की धमकी दे रहे हैं तो किसी को हथियारों की। वेनेजुएला पर अमेरिका ने हथियारों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडारों को लूटने के लिए वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना चाहता है।

अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर भी सेंशंस लगा दिए। इस बार अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल टैंकर गैरकानूनी तरीके से ईरान को तेल बेचने जा रहा था और हमने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। इस एक्शन के बीच रूस कूद पड़ा है। पुतिन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति माधुर से फोन पर बात की है और कहा है कि हम वेनेजुएला के साथ खड़े हैं।

रूस वेनेजुएला के लिए अमेरिका के खिलाफ खुलकर उतर चुका है। इसी बीच भारत और वेनेजुएला को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला अचानक भारत की शरण में पहुंचा था। वेनेजुएला की एक टीम भारत पहुंची और भारत को वो चीज देने का ऐलान कर दिया जो अमेरिका वेनेजुएला से लूटना चाहता है। वेनेजुएला ने भारत से कहा कि आप हमारे तेल के साथ-साथ हमारे देश में मौजूद क्रिटिकल मिनरल्स को भी निकालिए।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले में पांच पुलिसकर्मी घायल

पेशावर **(एजेंसी)**। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों द्वारा एक पुलिस चौकी पर किए गए हमले में कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

प्रवक्ता के बयान में कहा गया कि फितना अल ख्वारिज आतंकवादियों ने बृहस्पतिवार रात, बन्नू जिले के हावैद पुलिस क्षेत्र में स्थित शेख लैंडक पुलिस चौकी को निशाना बनाया। फितना अल खवारिज एक शब्द है जिसका इस्तेमाल सरकार प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े आतंकवादियों के लिए करती है। बयान में बताया गया कि पुलिसकर्मियों ने साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए समय रहते कार्रवाई की और हमले को नाकाम कर दिया। हमलावरों और पुलिस के बीच तीन घंटे तक गोलीबारी जारी रही। पुलिस के अनुसार, कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया और कई घायल हुए। गोलीबारी में पांच पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया।

बयान में कहा गया कि बन्नू के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) सज्जाद खान के निर्देश पर अतिरिक्त बल घटनास्थल पर पहुंचा और इलाके को घेर लिया। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है।

हत्यारे-फासिस्ट नहीं करा पाएंगे : बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों पर भड़की शेख हसीना की अवामी लीग

ढ़ाका। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग ने देश के चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को घोषित आम चुनावों को खारिज कर दिया है और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर 'हत्यारा फासीवादी' गुट होने का आरोप लगाया है। हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद पहली बार होने वाले संसदीय चुनाव 12 फरवरी को बांग्लादेश में होंगे।

बयान में अवामी लीग ने देश की सर्वोच्च चुनाव संस्था को अवैध सरकार का अवैध चुनाव आयोग बताया। उसने कहा कि यूनुस सरकार 'पारदर्शिता और निष्पक्षता' सुनिश्चित करने में विफल रही है, और साथ ही यह भी कहा कि चुनाव केंद्रित पार्टी अवामी लीग में बांग्लादेश की जनता के लिए खड़े होने की ताकत, साहस और क्षमता है।

बांग्लादेश अवामी लीग ने अवैध, कब्ज़ा करने वाले, हत्यारे-फासीवादी यूनुस गुट के अवैध चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम की बारीकी से समीक्षा की है। अब यह स्पष्ट है कि वर्तमान कब्ज़ा करने वाली सत्ता पूरी तरह से पक्षपाती है और उनके नियंत्रण में, एक निष्पक्ष और सामान्य वातावरण सुनिश्चित करना असंभव है जहाँ पारदर्शिता, तटस्थता और जनता की इच्छा प्रतिबिंबित हो सके।

यूक्रेन ने उड़ा दिए रूस के केमिकल प्लांट फैक्ट्री और रिफाइनरी, ट्रंप भी हैरान!

कीव **(एजेंसी)**। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया। केमिकल प्लांट, फैक्ट्री और रिफाइनरी पर ये मिसाइल अटैक किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन ने कहा कि कहा कि इस सप्ताह उसके लंबी दूरी के ड्रोन ने कैस्पियन सागर में एक प्रमुख अपतटीय तेल प्लेटफार्म पर हमला किया, जो पहले से अज्ञात एक मिशन था और यह उसके युद्ध को वित्तपोषित करने वाले रूसी ऊर्जा राजस्व को काटने के लिए बढ़ते अभियान में उसकी लक्ष्य सूची के नए विस्तार का संकेत देता है।

यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के एक सूत्र ने सीएनएन को बताया कि कैस्पियन सागर में तेल उत्पादन से संबंधित रूसी बुनियादी ढांचे पर यूक्रेन का यह पहला हमला है। उन्होंने इसे रूस को एक और चेतावनी बताया कि युद्ध के लिए काम कर रहे उसके सभी उद्यम वैध लक्ष्य हैं। लुकोइल के स्वामित्व वाला फिलानोव्स्की तेल प्लेटफार्म, कैस्पियन के रूसी क्षेत्र में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र होने का दावा करता है। सीएनएन ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए लुकोइल और रूसी रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है।

रूस की ऊर्जा सुविधाओं के खिलाफ यूक्रेन का व्यापक हमला अभियान 2024 की शुरुआत में शुरू हुआ, लेकिन अगस्त की शुरुआत से ही कीव ने इस प्रयास को और तेज कर दिया है। यूक्रेन के प्रतिबंध आयुक्त व्लादिस्लाव व्लासियुक इसे दीर्घकालिक प्रतिबंध कहते हैं, जिसका लक्ष्य रूस की सबसे बड़ी वित्तीय जीवनरेखा है। यूक्रेन अब रिफाइनरियों के अलावा तेल और गैस निर्यात अवसंरचना, पाइपलाइन, टैंकर और अब अपतटीय ड्रिलिंग अवसंरचना सहित कई लक्ष्यों को निशाना बना रहा है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)